● वर्ष-3
● अंक-117
रायपुर, रविवार
24 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› कमजोर लेखन से प्रभावित हुई...

डबल इंजन की सरकार होने से विकास में आयेगी तेजीः साय

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं रेल मंत्री से मुख्यमंत्री ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं केन्द्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्य के उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा भी उनके साथ थे। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री एवं मंत्रीगणों से छत्तीसगढ़ के हितों और विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रीगणों से छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के संबंध में मार्गदर्शन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार होने से छत्तीसगढ़ के विकास के कामों में तेजी आयेगी। विकास के कई काम पांच सालों से रूके पड़े थे। अब रूके हुए काम पूरे होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 2485.79 करोड़ की राशि जारी करने व सेंट्रल पूल में 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की अनुमति देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मिली राशि से समाज कल्याण की योजनाओं तथा अधोसंरचना विकास की योजनाओं के वित्तीय पोषण में मजबूती मिलेगी।

इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय मंत्रीगणों से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 'मोदी की गारंटी' पर त्वरित निर्णय लेकर अमल शुरू किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सरकार गठन होते ही प्रथम कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, राज्य के किसानों से किये वादे के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर 2023 से ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 'राष्ट्रीय सुशासन दिवस' के अवसर पर हम राज्य के 13 लाख से अधिक किसानों को दो साल का बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख रुपये का भुगतान करने जा रहे है। उन्होंने अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन, कृषक जीवन ज्योति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किए जाने के बारे में भी जानकारी दी।

भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक

2024 में वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य

नई दिल्ली। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों और कार्यक्रमों की रुपरेखा तय करने के लिए शुक्रवार को शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिन की बैठक आज समाप्त हो गई. बैठक दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुई. सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी करने, मिशन 2024 के लिए कमर कसने का आह्वान किया.

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी पूरे देश में महिला, युवा, किसान और गरीबों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी. प्रधानमंत्री मोदी जनवरी में देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे. बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 35 करोड़ वोट पाने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत विभिन्न योजनाओं के सात करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई है. अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी बीजेपी कार्यकर्ता

अपने-अपने इलाके के मंदिर में पूजन और लाइव प्रसारण की व्यवस्था करेंगे. 22 जनवरी के बाद हर राज्य से ट्रेन के जरिए लोगों को अयोध्या ले जाकर भगवान राम के दर्शन कराए जाएंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि राम मंदिर से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ज्यादा से ज्यादा साझा करें और लोगों से चर्चा करें. बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर हर एक मतदाता के संपर्क में रहने को कहा है. कहा गया है कि, कार्यकर्ता अपने-अपने बूथ के मतदाताओं के घर जाकर उनसे मिलें. भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं. बीजेपी की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव में %भारी% जीत हासिल करने पर टिकी हैं और इसके मद्देनजर पीएम मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10 प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा है. बैठक के समापन दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष स्तब्ध हो जाए. विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई की संभावना के बीच पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाले लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनावों की तुलना में पार्टी के वोट प्रतिशत में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का आह्वान किया. सन 2019 के चुनाव में बीजेपी को 37 प्रतिशत से अधिक वोट मिले थे जबकि उसके नेतृत्व वाले एनडीए को करीब 45 प्रतिशत वोट मिले थे. सन 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में अपने वोट प्रतिशत को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं.

भाजपा की राष्ट्रीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण ने दी जानकारी

रायपुर। दिल्ली में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश भाजपा संगठन की ओर से विचार व्यक्त किए। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी पर अमल शुरू हो गया है। कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी देकर बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने अटलजी की जयंती राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष अवसर पर राज्य के किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने छत्तीसगढ़ में हुई शानदार जीत के बारे में कहा कि अविभाजित मध्यप्रदेश के इतिहास के समय से अब तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की यह सबसे बड़ी जीत। उन्होंने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं और महिलाओं ने भी जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध के विषय को लगातार उठाया। इसके खिलाफ जन आंदोलन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्षजेपी नड्डा, देश के गृहमंत्री अमित शाह सहित सभी के मार्गदर्शन हेतु प्रदेश भाजपा की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया।बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा सह प्रभारी नितिन नबीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे।

कांग्रेस में फेरबदलः पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी नियुक्ति

उप्र की प्रभारी की भूमिका निभा रही प्रियंका के जगह अविनाश पांडे

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी संगठन में शनिवार को बड़ा बदलाव कर दिया गया है. राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पार्टी का महसचिव नियुक्त करने के साथ ही छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव करते हुए 12 महासचिवों और 12 प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है.

प्रियंका गांधी पिछले करीब पांच साल से उत्तर प्रदेश की प्रभारी की भूमिका निभा रही थीं. अब प्रियंका गांधी के स्थान पर पार्टी महासचिव अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है. कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव बने रहेंगे तथा महासचिव जयराम रमेश भी पार्टी की संचार विभाग के प्रभारी की जिम्मेदारी

निभाते रहेंगे. अजय माकन पार्टी के कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे. उनके साथ दो नेताओं मिलिंद देवरा और विजय इंदर सिंघला को संयुक्त कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

रणदीप सिंह सुरजेवाला से मध्य प्रदेश का प्रभार वापस लिया गया है. अब वे सिर्फ कर्नाटक के प्रभारी रहेंगे. उनके स्थान पर जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश के प्रभार की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. जितेंद्र सिंह पहले से ही असम के प्रभारी हैं. राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को महसचिव नियुक्त करने के साथ ही छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है. महासचिव कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ से हटाकर उत्तराखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप गई है. सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बने रहेंगे.

भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं का गुट है विपक्षी गठबंधन

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले नेताओं का एक गुट करार दिया जिनके पास कोई साझा विचारधारा या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ठाकुर ने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी हार की हताशा के कारण ही संसद के शीतकालीन सत्र को बाधित किया। संसद का शीतकालीन सत्र बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने कहा, कहां है गठबंधन? वे पंजाब में जूझ रहे हैं, वे अन्य राज्यों में जूझ रहे हैं। वे एक स्वर में बात नहीं कर सकते। ये भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों का एक गुट है, जो एकसाथ आ गए हैं। ठाकुर ने कहा, उनके पास कोई साझा विचारधारा नहीं है, उनका कोई एक साझा कार्यक्रम नहीं है और न ही उनका कोई साझा उम्मीदवार है। कोई इंडिया गठबंधन नहीं है।

प्रमुख समाचार

'नकली' दवा विवाद : भाजपा ने दिल्ली के मंत्री भारद्वाज को बर्खास्त करने, कांग्रेस ने जांच की मांग की

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 'नकली' दवाओं की कथित आपूर्ति पर उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को बर्खास्त करने की शनिवार को मांग की। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने कहा कि यह ''गंभीर मामला'' है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सचदेवा ने कहा, ''हमारे पास लैब और सतर्कता रिपोर्ट है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जा रही दवाओं के नमूने फेल हो गए हैं। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें।'' दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जांच तेजी से पूरी होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि घटिया दवाओं का मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है क्योंकि इससे लोगों की जान को खतरा है। उन्होंने कहा, ''इसके लिए

हिमाचल प्रदेश: भाजपा विधायकों ने बागवानी करने वाले किसानों से किये गये वादों को पूरा करने की मांग की

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बागवानी करने वाले किसानों से किये गये वादों को पूरा करने की मांग करते हुए सेब की पेटियां लेकर शनिवार को विधानसभा परिसर में पहुंचे। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले किये गये 10 गारंटी से जुड़े वादों को कथित रूप से पूरा नहीं किये जाने को लेकर भाजपा विधायक राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने यहां तपोवन में सत्र के पाचवें दिन की कार्यवाही की शुरुआत से पहले विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने वादा किया था कि बागवानी करने वाले किसानों को उनकी ऊपज का निश्चित दाम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठाकुर ने फिर कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादे कर लोगों को 'गुमराह' किया एवं उन्हें 'ठगा' लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अपनी गारंटी को भूलने नहीं देगी।

असम में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट को लेकर 83 उम्मीदवारों ने दिया आवेदन

नई दिल्ली। असम के तीन मौजूदा सांसद उन 83 कांग्रेस सदस्यों में शामिल हैं, जिन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी से टिकट मांगा है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। नागांव सीट से लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई ने इस निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ने की मांग करते हुए आवेदन किया है जबकि बरपेटा से सांसद अब्दुल खालिक ने भी अपना आवेदन दिया है, हालांकि उन्होंने अपनी पसंद की सीट का जिक्र नहीं किया है। लोकसभा में असम की कलियाबोर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले गौरव गोगोई ने नागांव, काजीरंगा और जोरहाट सीट से अपना आवेदन भेजा है। असम में हुई परिसीमन प्रक्रिया में उनकी सीट समाप्त हो गई है। कांग्रेस द्वारा साझा की गई सूची के अनुसार, राज्य विधानसभा में विपक्ष के उपनेता रकीबुल हुसैन ने भी नागांव निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना आवेदन दाखिल किया है। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हुसैन सामागुरी से विधायक हैं, जो नागांव के अंतर्गत आता है। राज्य कांग्रेस इकाई ने 11 दिसंबर से प्रति आवेदन एक लाख रुपये शुल्क के साथ इच्छुक उम्मीदवारों से भरे हुए आवेदन पत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

लेखा नियामक ने ऑडिट मामले में क्षेत्र की चार बड़ी कंपनियों के खिलाफ चूक के मामले पाये

नई दिल्ली। लेखा नियामक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने ऑडिट गुणवत्ता जांच के दौरान क्षेत्र से जुड़ी चार बड़ी कंपनियों के खिलाफ कुछ चूक के मामले पाये हैं। प्राधिकरण ने डेलॉयट, हास्किन्स एंड सेल्स, बीएसआर एंड कंपनी, एसआरबीसी एंड कंपनी और प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स - कंपनियों का ऑडिट गुणवत्ता निरीक्षण किया। बीएसआर एंड कंपनी एलएलपी और एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी क्रमशः केपीएमजी और ईवाई से जुड़ी कंपनियां हैं। पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, ईवाई और केपीएमजी ऑडिट क्षेत्र में चार प्रमुख वैश्विक कंपनियां हैं। इन्हें 'बिग 4' के रूप में भी जाना जाता है। एनएफआरए ने शुक्रवार को अलग-अलग रिपोर्ट में कहा कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ऑडिट कंपनियों का निरीक्षण पिछले साल दिसंबर में शुरू किया गया था। इसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था।

पुंछ में तीन लोगों की मौत के मामले में राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में कई राजनीतिक दलों ने शनिवार को प्रदर्शन किया और पूछताछ के लिए सेना द्वारा कथित तौर पर पकड़े गए तीन लोगों की रहस्यमयी हालात में मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि सेना ने पूछताछ के लिए 15 लोगों को पकड़ा था, जिनमें से तीन की मौत हो गई जबकि बाकी बचे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। महबूबा ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, पुंछ हमले के बाद सेना ने पूछताछ के लिए टोपा पीर गांव से 15 लोगों को पकड़ा था, जिनमें से तीन लोगों के शव मुठभेड़ स्थल के समीप से बरामद किए गए, जिन पर चोट के गंभीर निशान थे। बाकी बचे 12 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासन से तीनों मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा देने को मंजूरी प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा, मैंने उपराज्यपाल से मामले की जांच पूरी होने तक तीनों परिवारों को राहत के रूप में 50-50 लाख रुपये प्रदान करने और अस्पताल में भर्ती घायलों को पांच-पांच लाख रुपये देने का अनुरोध किया है। उनके परिवार बेहद गरीब हैं।

बंटा हुआ विपक्ष, बीजेपी का प्रचंड होता दायरा, आंकड़ों से समझें आगामी आम चुनाव का गुणा-गणित

अभिनय आकाश

साल 2024 के आम चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे आने के बाद से लोकसभा परिणामों को लेकर गुणा-गणित का दौर भी शुरू हो गया है। पिछले दो चुनावों का अवलोकन करें तो के विपरीत 2019 के लोकसभा चुनावों में अधिकांश सीटें 50 प्रतिशत से अधिक वोटों के साथ जीती गईं। 2014 जहां अधिकांश जीत 50 प्रतिशत से कम थीं। 2019 के चुनावों में भी 2014 से उलट स्थिति देखी गई, जिसमें अधिकांश सीटों (341) पर 50 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर हासिल किया गया, जो 2014 में 200 से उल्लेखनीय वृद्धि है।

बीजेपी का प्रचंड होता दायरा

जिस भाजपा के बारे में कहा जाता था कि %बैठक, भोजन और विश्राम... भाजपा के यह तीन काम% इस धारणा को 2014 और फिर 2019 के चुनाव में ध्वस्त किया। 182 की चौखट पर हांफने वाली बीजेपी अपने बूते बहुमत के आंकड़े को पार किया। दसों दिशाओं से आने वाली जीत आती चली गई। मोदी के अश्वमेध रथ पर अमित शाह जैसा सारथी घर-घर करते हुए आगे बढ़ा तो उसकी चाप से हिन्दुस्तान का मुकद्दर रचने चले नए सिकंदर की जयजयकार सुनाई पड़ने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बढ़ते प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए 2019 में 50 प्रतिशत से अधिक वोटों के साथ 224 सीटें हासिल कीं, जो 2014 में 136 से काफी अधिक है।

बंटा हुआ विपक्ष

इसके विपरीत, विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, खंडित रही। कांग्रेस की उच्च अंतर वाली जीत 2014 में 37 सीटों से घटकर 2019 में केवल 18 रह गई, जो उसके घटते प्रभाव को दर्शाती है। आगामी आम चुनाव से पहले, भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निर्णायक जीत हासिल की, जो इन प्रमुख राज्यों में मजबूत पकड़ का संकेत देती है।

जीत क्यों इतना मायने रखती है

मतदान पैटर्न में बदलाव में बदलाव भी देखने को मिला। विशेषकर भाजपा की अधिक मार्जिन से जीत भारत में एक परिवर्तनकारी राजनीतिक परिदृश्य का संकेत देता है। भविष्य की चुनावी रणनीतियों को समझने और मतदाता प्राथमिकताओं को विकसित करने के लिए इन बदलावों को समझना महत्वपूर्ण है।

आंकड़ों से समझें

2019 के चुनावों ने भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जिसने 436 सीटों पर चुनाव लड़कर 303

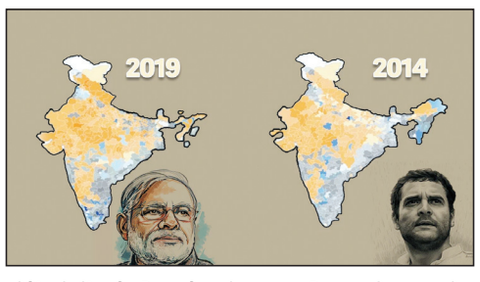

सीटें जीतीं, जो कि उल्लेखनीय 70 प्रतिशत जीत दर थी। इस चुनावी सफलता को पार्टी की कुल वोट हिस्सेदारी 37.4 प्रतिशत और जिन सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां और भी अधिक प्रभावशाली 46.1 प्रतिशत वोट शेयर पर आधारित था। इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी ने अपने 2014 के प्रदर्शन के अनुरूप 19.5 प्रतिशत वोट शेयर बनाए रखा, जो 2019 में 52 सीटों में तब्दील हो गया।

क्यों महत्वपूर्ण है हिंदी बेल्ट में मिली जीत

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी जीत भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2024 में एक और जीत की प्रस्तावना के रूप में वर्णित किया है। इन राज्यों में भाजपा का लोकसभा वोट शेयर उसके विधानसभा चुनाव परिणामों से काफी अधिक है, जो मोदी इफेक्ट को दर्शाता है। इस बीच, कांग्रेस पार्टी को आम तौर पर विधानसभा चुनावों की तुलना में लोकसभा में कम वोट शेयर मिलते हैं। 2019 के चुनावों में भाजपा के प्रभुत्व के बाद 2014 में भी इसी तरह की सफलता मिली, जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एकल-पार्टी बहुमत की ओर बदलाव का संकेत है। यह बदलाव उस पृष्ठभूमि में किया गया है जहां विपक्ष, मुख्य रूप से कांग्रेस, बिखरा हुआ है और भाजपा की कथा और चुनावी रणनीतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में असमर्थ प्रतीत होता है।

मजबूत, एकजुट विपक्ष बनाने में नहीं मिल रही सफलता

भाजपा की बढ़त 2014 से 2019 तक उसके वोट शेयर में वृद्धि से स्पष्ट है, जो विभिन्न जनसांख्यिकी में उसकी बढ़ती अपील का संकेत है। आंतरिक चुनौतियों और बदलते राजनीतिक परिदृश्य से जूझ रही कांग्रेस ने उसी अवधि के दौरान अपना प्रभाव कम होते देखा। 2024 के चुनावों के लिए पार्टियों की तैयारी के दौरान सामने आने वाली रणनीतियों और आख्यानों को समझने के लिए भाग्य में यह बदलाव महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को पिछले चुनाव की तुलना में अधिक सीटें मिलने के बावजूद, वे अभी भी एक मजबूत, एकजुट विपक्ष बनाने से पीछे रह गए। 2019 के चुनाव परिणामों को एक-दलीय प्रभुत्व युग के सुदृढीकरण के रूप में देखा जा सकता है, जो कांग्रेस के शुरुआती प्रभुत्व की याद दिलाता है।

नेताओं का क्या है कहना

3 दिसंबर को पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजे सुशासन और विकास की राजनीति के लिए भारत के समर्थन को दर्शाते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हमारा 40 प्रतिशत वोट शेयर बरकरार है। 2024 की प्राथमिकताओं पर, चिदंबरम कहते हैं, जाति जनगणना मायने रखती है.

सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ फोर्स पर नक्सलियों ने की फायरिंग

■ जवानों ने नक्सलियों को गोली लगने का किया दावा

सुकमा। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित सुकमा के गोगुंदा इलाके में सुरक्षाबल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान 3 नक्सली घायल हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि सुकमा डीआरजी, दंतेवाड़ा डीआरजी, सीआरपीएफ द्वितीय बटालियन और सीआरपीएफ 111 बटालियन की एक संयुक्त टीम गोगुंडा इलाके में सर्चिंग पर निकली हुई थी। इसी दौरान जंगल में पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। हमला होते देख जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 3 नक्सलियों को घायल किया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से फरार हो गए। बताया गया है कि जवान अभी भी जंगल में घायल नक्सलियों को घेरने की तैयारी कर रहे हैं।

22 दिसंबर को ही माओवादियों ने भारत

बंद का ऐलान किया था। इस दौरान बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। नारायणपुर ओरछा मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा। बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में भी नक्सलियों ने रोड जाम किया। सुकमा जिले का चिंतलनार से किस्टारम मार्ग भी बंद रहा। इससे पहले माओवादियों ने बीजापुर जिले में दो यात्री बसों को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही सुकमा जिले में भी नेशनल हाईवे 30 में एक यात्री बस दो ट्रेलर वहां वह एक चार पहिया वाहन को भी आपके हवाले कर दिया था।

नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज, 30 फीट नक्सली स्मारक ध्वस्त, डीआरजी और महिला कमांडो की कार्यवाही

बीजापुर। बीजापुर में नक्सलियों के मांद में घुसकर जवानों ने नक्सलियों को मात देते हुए उनके द्वारा जंगल में बनाये गए नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया हैं। जवानों की इस कार्रवाई में महिला कमांडो भी शामिल रहीं। बीजापुर पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को गंगालूर थाना क्षेत्र के डुमरीपालनार में स्थापित कैम्प से डीआरजी बीजापुर, महिला कमांडो व डीआरजी दंतेवाड़ा की संयुक्त टीम नक्सली विरोधी अभियान पर निकली थी। नक्सलियों ने डुमरीपालनार के जंगल में करीब 30 फीट ऊंचा नक्सली स्मारक बना रखा था। जिसे अभियान पर निकले जवानों की संयुक्त टीम ने उक्त नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया।

केदार को मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर बस्तर प्रभारी ने जाहिर की खुशी

बीजापुर। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने उत्तर से मुख्यमंत्री के बाद दक्षिण से जगदलपुर विधायक किरण देव के हाथ पार्टी की कमान सौंपने के साथ मंत्रिमंडल में नारायणपुर से विधायक केदार कश्यप को जगह दी है। भाजपा के इस निर्णय का बस्तर के सभी दिग्गज भाजपाईयों ने इसका स्वागत किया है। सत्तासीन होने के बाद केदार कश्यप को मंत्रीमंडल में पुन: स्थान मिलने पर बस्तर प्रभारी जी वेंकट ने खुशी जाहिर करते बस्तर की समस्त जनता को बधाई दी है। साथ उन्होंने जगदलपुर विधायक किरण देव को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है।

जी वेंकट ने बताया कि किरण देव सामान्य वर्ग से आते हैं। इससे पहले आदिवासी और ओबीसी को अध्यक्ष के रूप में मौका दिया गया है। आदिवासी अध्यक्ष के रूप में नंदकुमार साय, विष्णुदेव साय के अलावा विक्रम उसेंडी अध्यक्ष रह चुके हैं। ओबीसी वर्ग से धरमलाल कौशिक और अरूण साव अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले सामान्य वर्ग से डॉ रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं केदार कश्यप एक बार फिर मंत्री बनाए गए हैं। इस पर बस्तर जी वेंकट ने कहा कि बस्तर से बड़ी जिम्मेदारी भाजपा की

दुरूगामी सोच को दर्शाता है, जनता की मांग का भाजपा ने सम्मान किया है। ना सिर्फ नारायणपुर विधानसभा में रूके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। बल्कि बस्तर की जनता की अपेक्षानुरूप काम में तेजी आएगी।

उनका यह भी कहना है कि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बस्तर के जमीनी हालात को कोई नजदीक से समझ सकता है तो केवल एक आदिवासी। अब चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। लिहाजा आदिवासियों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उनका सर्वांगीण विकास होगा। इसी ध्येय को लेकर ही भाजपा ने बस्तर से एक को पार्टी की कमान तो वरिष्ठ नेता केदार कश्यप को मंत्री मंडल में जगह देकर बस्तर की जनता का सम्मान किया है।

समय पर धान उठाव होने से करोड़ों रु. का हो रहा फायदा

बलरामपुर। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 49 धान उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है। पिछले वर्ष भी समय पर धान का उठाव होने के कारण संग्रहण केंद्रों में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। वहीं इस वर्ष भी समय पर उठाव हो रहा है जिससे संग्रहण केंद्र भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में शासन को करोड़ों रुपये की बचत होगी। जहां पहले संग्रहण भी केंद्र भेजने में एवं उसके रखरखाव में करोड़ों रुपए खर्च होते थे उससे अब बचत होगी। समय पर धान का उठाव होने पर सहकारी समितियों को भी फायदा मिल रहा है।

गौरतलब है कि अब तक जिले के 49 धान उपार्जन केंद्रों में 23130 टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं 11465 टन धान का उठाव भी हो चुका है। सहकारी समितियां से जिला विपणन अधिकारी से एग्रीमेंट में 72 घंटे में उठाओ का प्रावधान होता था परंतु उठाओ महीना भी नहीं हो पाता था यहां तक की कई बार सहकारी समितियां के द्वारा उठाव के लिए उच्च अधिकारियों को पत्राचार भी किया जाता था इसके बाद भी उठाव की स्थिति नहीं सुधर पाती थी। लेकिन बीते वर्ष से उठाव समय पर होने से इसका फायदा सहकारी समितियों को जहां मिल रहा है वहीं शासन को करोड़ों रुपये की बचत हो रही है।

सन 2021-22 में 21 लाख टन गम्हरिया एवं डकवा में तीन लाख टन धान का संग्रहण किया गया था इसके रखरखाव एवं परिवहन में करोड़ों रुपये खर्च हुए थे।

दुर्ग और भिलाई में डायरिया का कहर

दुर्ग। शहर के खुर्सीपारा इलाके के गौतम नगर में डायरिया का प्रकोप बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग के सैंपल जांच में अब तक इलाके में 118 डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। डायरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पानी के सैंपल को जांच के लिए लैब भिजवाया है। नगर निगम की टीम ने एहतियात के तौर पर इलाके में पानी की सप्लाई बंद कर दी है। इलाके में पानी के टैंकरों से लोगों को साफ पानी की सप्लाई फिलहाल की जा रही है।

गौतम नगर इलाके में बीते 6 दिनों से डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। गंभीर रुप से बीमार 6 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हल्के और कम लक्ष्ण वाले मरीजों को घर पर भी रखा गया है। जिन मरीजों का घर पर इलाज चल रहा है उनको कहा गया है कि वो डॉक्टरों के संपर्क में रहें। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हालात पर नजर रख रही है।

70 साल से नहीं बना आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में हद हो गई है। राज्य को बने 23 साल से ज्यादा हो गए। देश को आजाद हुए सात दशक यानि की 70 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन बलौदाबाजार के कसडोल के आदिवासियों की अनदेखी लगातार हो रही है। सात दशक में भारत में न जाने कितनी सरकारें बदली, 23 साल में छत्तीसगढ़ में 6 सरकारें बन गई। लेकिन कसोडल के टिपरुंग के सोंझरी आदिवासियों की किस्मत नहीं बदली। इस आदिवासी समाज के लोंगों का अब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। जिसकी वजह से सोंझरी ट्राइब के लोग विकास की मुख्यधारा में जुड़ने से महरूम हैं।

टिपरुंग में रहने वाले सोंझरी समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र एक दो साल से नहीं बल्कि 70 साल से नहीं बन पा रहा है। यही वजह है कि इस जनजाति समाज के बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए। कई बच्चों ने सिर्फ पांचवी और कई बच्चों ने बमुश्किल 12वीं तक की ही पढ़ाई कर पाए। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण सोंझरी जनजाति

समाज के लोगों को कई शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई बार की गई शिकायत

जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई बार सोंझरी जनजाति समाज के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस या अन्य जगह पर शिकायत की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न तो किसी नेता और जनप्रतिनिधि ने इनकी आवाज उठाई है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से सोंझरी समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। आगे पढ़ाई में भी किसी तरह की सहूलियत नहीं मिल पा रही है।

लखन सोंझरी ने कहा कलेक्टर, मंत्री सहित तमाम जिम्मेदारों को हमने जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत की है। लेकिन हमारा आवेदन सिर्फ दफ्तर और दफ्तर में घूम रहा है। न तो अधिकारी ध्यान देते हैं, न ही नेता और विधायक इस समस्या पर गंभीर हैं।

सोनझरी समाज के लोग साल 1942 से यहां निवास कर रहे हैं। सोंझरी ट्राइब आदिवासी समूह की 42 जनजातियों में शामिल हैं। राजपत्र में सोनझोला, सोनझारी, सोनझरिया, सोनझरा, सोनझला, सोनझरी और सोनकला जैसी ट्राइब को नहीं दर्शाया गया है। जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। सर्व सोंझरी समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा पत्र लिखकर राज्य सरकार एवं भारत सरकार से निवेदन भी किया गया है। लेकिन अब तक इनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि आदिवासी सीएम के राज में इस समाज का कल्याण हो पाता है या नहीं।

पीएम आवास योजना से मिला टिमनार की टेटकी को सुंदर आशियाना

■ मकान का सपना हुआ साकार

नारायणपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों, पिछड़ों और महिला मुखिया परिवारों के लिए प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत टिमनार की निवासी श्रीमती टेटकी यादव प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाकर सपरिवार अपने स्वयं के आवास में हंसी खुशी से रह रही हैं।

श्रीमती टेटकी यादव ने बताया कि वे खेती किसानी करती हैं, उनकी आय कम होने के कारण कच्चे मकान में रहना पड़ता था, उस घर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पूरे परिवार का सपना था की एक पक्का घर बना पाएं, जहां सपरिवार बिना किसी परेशानी के रह सके। प्रधानमंत्री आवास योजना उनके जीवन में वरदान बनकर आई, जिसकी सहायता से उनका पक्का घर बनाने का सपना पूरा हो पाया। श्रीमती यादव ने बताया कि बहुत दिनों से वे अपना स्वयं का मकान बनाने की सोच रहे थे, लेकिन आर्थिक परेशानियों की वजह से मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे थे। पहले सीट, खपरैल वाले कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ गुजर-बसर करते थे। कच्चे मकान में बरसात के दिनों में बहुत परेशानी होती थी, छप्पर से टपकता पानी, दीवार में सीलन से

परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

श्रीमती यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा करने के पश्चात उन्हें आवास की स्वीकृति मिल गई। इसके पश्चात हितग्राही के खाते में आवास निर्माण प्रारंभ करने के लिए राशि की प्रथम किश्त जारी की गई एवं आवास का निर्माण प्रारंभ हो गया। आवास निर्माण के साथ ही किश्त की बाकी राशि भी खाते में आ गई। आज उनका आवास पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपनी पूरी परिवार की ओर से इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा छत्तीसगढ़ सरकार का आभार जताया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

विधायक खुद पहुंचे जनता के बीच, सड़क पर सुनी समस्या

बिलासपुर। प्रदेश में नई सरकार के आते ही बदलाव की बयार बह रही है। इसका नजारा बेलतरा विधानसभा में देखने को मिला, जहां विधायक सुशांत शुक्ला की, जिन्होंने शनिवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान चिंगराजपारा, डबरीपारा, चांटीडीह में लोगो से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी एवं निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। विधायक सुशांत शुक्ला से चर्चा के दौरान लोगों ने नाली निर्माण, नाली साफ सफाई, खुले नाले के उप्पर स्लैब निर्माण, नदी किनारे कचड़े डंप हो रहे है वो बंद हो, मंदिरों में शेड निर्माण, सुलभ शौचालय की साफ सफाई एवं रिपेयरिंग, सामुदायिक भवन की रंग रोगन की समस्या बताई। मॉर्निंग वॉक से लौटते समय विधायक सुशांत शुक्ला ने शारदा गैस एजेंसी कपिल नगर के पास 300 से अधिक महिलाओं और पुरुषों की भीड़ को देख उनकी समस्या सुनी, तुरंत कॉल कर गैस एजेंसी मालिक एवं नोडल अधिकारी से केवाईसी प्रकिया को सरल एवं स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए।

सड़क निर्माण में बडा हादसा सेंट्रिंग गिरने से मजदूर दबे

धमतरी। धमतरी से विशाखापत्तनम तक भारतमाला परियोजना के तहत हो रहे सडक निर्माण में एक बडा हादसा हो गया। जहां सेंट्रिंग गिरने से तीन मजदूर दब गए। जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर केरेगांव पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि भारतमाला परिजयोजना के तहत धमतरी से विशाखापत्तनम तक छह लेन सडक का निर्माण हो रहा है। जंहा केरेगांव के पास पुल निर्माण के लिए सेंट्रिंग बांधा गया था जो अचानक ढह गया जिसके चलते नीचे काम कर रहे तीन मजदूर दब गए। आनन-फानन में तीनों मजदूरों को निकाला गया जिसमें से एक मजदूर अमेरिका महतो बिहार निवासी की मौत हो गई। जबकि घायल दो मजदूरों को इलाज के लिए धमतरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल केरेगांव पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

जिमनास्टिक खिलाड़ियों को ट्रेन में नहीं मिली सीट

गौरेला पेंड्रा मरवाही। खेल भावना बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा अभियान यहां पर कागजी साबित हो रहा है। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में राष्ट्रीय स्तर के जिमनास्टिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दिल्ली ले जाया गया लेकिन अव्यवस्थाओं को लेकर बच्चे इतने दुखी हैं कि दोबारा बाहर जाने के नाम से उन्हें डर लग रहा है। इन बच्चों को दिल्ली से पेण्ड्रा तक का सफर बोगी के वॉशरूम के पास बैठकर करना पड़ा। वहीं जो बच्चों को लेकर दिल्ली गए थे वो वापस आ गए। दरअसल 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता में जिले से जिमनास्टिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने दिल्ली गये हुए थे। 51 खिलाड़ियों का यह दल 22 दिसंबर को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली से वापस छत्तीसगढ़ आया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 51 खिलाड़ियों की समस्या यह थी कि उनके दल प्रबंधक ने स्लीपर कोच में रिजर्वेशन करवाया पर टिकट कन्फर्म नहीं हो पाया।

कोरबा में एक क्वार्टर में लगी आग, सामान जलकर खाक

कोरबा। कोरबा की एक कॉलोनी में आग लगने की खबर सामने आई है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक क्वार्टर में भीषण आग लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक, तड़के सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। आगजनी के बाद कॉलोनी में हड़कप मच गया। हादसे के बाद यहां से लोग आसपास के मकान छोड़ भागे। शार्टसर्किट के चलते आग लगना बताया जा रहा है। आगजनी में घर पर रखी आलमारी, कूलर,पंखा बेड समेत घर का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर पहुंचे दो दमकल वाहनों की मदद से भारी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया। एसबीआई बैंक में चपरासी का काम करने वाले मनोज कुमार देवांगन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है। देर रात वो खाना खा कर सो गया। सुबह चार बजे लगभग अचानक घर पर धुआं उठता देख वो अपने कमरे से बाहर निकला और चिख पुकार मचाने लगी। आसपास कॉलोनी वासियों का दरवाजा खटखटाया देखते ही देखते आग की लपेट बढ़ने लगीं।

रिसाव के कारण बोहला बांध का जलस्तर हो रहा कम

बलरामपुर। बलरामपुर रामानुजगंज नगर के जल स्तर को बनाए रखने वाला रामानुजगंज जलाशय(बोहला बांध) का लगातार जल स्तर गेट के लीकेज होने के कारण कम होता जा रहा है। जिस प्रकार से रामानुजगंज जलाशय से पानी निकल रहा है यदि इसी रफ्तार से पानी निकलता रहा और जल संसाधन विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो फरवरी मार्च आते आते रामानुजगंज जलाशय की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी ऐसे में नगर में भीषण जल संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। गौरतलब है कि 1980 के करीब रामानुजगंज जलाशय का निर्माण किया गया था जिसे सभी बोहला बांध के नाम से जानते है। 1980 के पूर्व नगर में भीषण जल संकट उत्पन्न हो जाता था वहीं जल स्तर भी गर्मी में काफी नीचे चला जाता था परंतु रामानुजगंज जलाशय के निर्माण के बाद यहां जब से पानी रुकना शुरू हुआ तब से नगर के जल स्तर में सुधार हुआ। लेकिन बीते दो दशकों से जल संसाधन विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण यह पानी का भरपूर जमाव नहीं हो पा रहा है।

सुशासन दिवस पर बेमेतरा में होगा कवि सम्मेलन

■ नवागढ़ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री श्री दयाल दास बघेल होंगे, वही बेमेतरा और साजा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक होंगे

■ मुख्य अतिथि किसानों को लंबित बोनस राशि का वितरण करेंगे

बेमेतरा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व.श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनायी जायेगी। प्रातः 10 बजे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व श्री अटल बिहारी बाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलन पश्चात जनप्रतिनिधियों एवं आमजनता द्वारा सुशासन स्थापित करने संकल्प लिया जाएगा। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को ज़िले के चारों विकासखंडों में

मुख्य अतिथियों द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2014.15 एवं 2015.16 में धान बेचन वाले कृषकों के लम्बित बोनस राशि वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी है। मंत्री श्री दयाल दास बघेल नवागढ़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। बेमतरा में मुख्य अतिथि विधायक श्री दीपेश साहू और साजा ब्लॉक में मुख्य अतिथि विधायक श्री ईश्वर साहू किसानों को बोनस राशि प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। शाम 06 बजे से अटल संध्या का मंडीपरिसर में आयोजन किया जाएगा। जिसमें कवि सम्मेलन अटल जी की कविता पाठ, अटल विचार संगोष्टि आयोजित की जाएगी।

ज़िला मुख्यालय बेमेतरा में प्रातः 10 बजे जय स्तंभ चौंक में जनप्रतिनिधियो एवं आम जनता के द्वारा माल्यार्पण, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व श्री अटल बिहारी बाजपेयी को नमन किया जाएगा। शाम 6 बजे कृषि उपज मंडी बेमेतरा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जावेगा। जिसमें रामानन्द त्रिपाठी (हास्य व्यंग्य) कवि एवं मंच संचालक बेमेतरा, पद्मलोचन शर्मा मुहफट (हास्य पैरोडी) कार राजनांदगांव मनीराम साहू मितान (हास्य व्यंग्य) सिमगा, ईश्वर साहू अरुण (छत्तीसगढ़ी वीर रस), ठेलका प्रियंका गुप्ता प्रिया (श्रृंगार रस), खरसिया अभिषेक पांण्डे युवा कवि/वक्ता कवर्धा द्वारा प्रस्तुती दी जावेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने शहर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों प्रबुद्ध नागरिक पत्रकार एवं आमजन सादर आमंत्रित है।

150 साल पुराने पीपल के वृक्ष को काटा, सैकड़ों पक्षियों की मौत

धमतरी। स्वस्थ्य जीवन के लिए पर्यावरण की अहम भूमिका होती है, इसके लिए पेड़ पौधों को नहीं काटने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा ही एक मामला धमतरी जिले में सामने आया है जहाँ धमतरी शहर में करीब 150 साल पुराने पीपल वृक्ष की शाखाओं को काट दिया गया और उन शाखाओं में घोसला बनाए सैकड़ों पक्षीयों की मौत होने का मामला सामने आया है।

इस घटना से इलाके में हडकंप मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत पक्षियों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि धमतरी शहर के सदर मार्ग में करीब 150 साल पुराना पीपल का वृक्ष है। जिसमें प्रजनन काल पर आए पनडुब्बी प्रजाति की कॉर्मोरेंट पक्षियों ने घोसला बनाया हुआ था। वहीं आस-पास के लोगों ने बिना राजस्व, नगर निगम और वन विभाग से अनुमति लिए वृक्ष की शाखाओं को काट दिया। जिससे सैकडों की तदाद में पक्षियों की मौत हुई है।

इस मामले में नगर निगम का कहना है कि शहर के अंदर पेडों को काटने की अनुमति राजस्व विभाग देता है और पक्षियों के मारे जाने की सुचना निगम के पास नही है। दूसरी ओर वन विभाग का कहना है कि वृक्ष की शाखाओं को कटाने की किसी तरह की कोई अनुमित नहीं ली गई है। कहा कि वन विभाग की तरफ से जांच कराई जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने विस अध्यक्ष डॉ. सिंह से की मुलाकात

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से

भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी संगठन राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने आज उनके गृह निवास पर भेंट कर राज्य में नई सरकार के गठन पर प्रसन्नता जताई और उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी. प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें ज्ञापन देकर राज्य सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों संबंधित मामलों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. विधानसभा अध्यक्ष ने इन मामलों पर नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कही. प्रतिनिधि मंडल में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, संघ के प्रदेश महामंत्री एके चेलक, कोषाध्यक्ष टीआर देवांगन, संयुक्त महामंत्री जीआर बसोंने,प्रांतीय सचिव डॉ विनोद वर्मा, राजपत्रित प्रकोष्ठ के संयोजक एके सोनी, स्वास्थ्य विभाग के प्रांतीय संयोजक सीआर साहा, जिला रायपुर के अध्यक्ष ओपी पाल, नागेंद्र सिंह, अशोक घोष, मन्नूलाल भतपहारी, नरेंद्र सोनकर आदि शामिल थे.

मुख्यमंत्री साय ने प्रेमलता शर्मा के निधन पर दुख प्रकट किया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं दैनिक अग्रदूत के स्थानीय संपादक श्री के.के. शर्मा की माता श्रीमती प्रेमलता शर्मा के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने श्रीमती प्रेमलता शर्मा के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से श्रीमती शर्मा के परिवारजनों को दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।

अपना वोट बैंक बढ़ाने कांग्रेस धर्मांतरण को देती रही बढ़ावा : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जोरों से धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता के ऊपर ही कार्यवाही हो जाती थी। कांग्रेस अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा देते रही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो धर्मांतरित हो जाता है, वह भाजपा से अलग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, न नहीं होने देंगे। धर्मांतरण पर रोक लगेगी। प्रदेश में नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 15 वर्षों में जब हमारी सरकार थी, तो नक्सलवाद के खिलाफ हम मजबूती से लड़े। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तब उनको बढ़ावा मिला। वो लोग कहते थे कि हमारी सरकार आ गई। जब से यहां सरकार बदली है, उनमें बौखलाहट आ गई है। वो कायराना हरकत भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने जैसे ही अधिकारियों को निर्देशित किया है, पुलिस एक्शन में आ गई है। नक्सली पकड़े भी गए हैं। हमारे देश के गृहमंत्री भी नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे

झीरम घाटी हत्याकांड के वांटेड 19 नक्सलियों की तलाश में जुटी एनआईए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वांटेड माओवादियों की तलाश में एनआईए जुट गई है। एनआईए ने 19 नक्सलियों की सूची जारी की है। ये सभी नक्सली देश का दूसरा सबसे बड़ा नक्सल हमला झीरम घाटी हत्याकांड के वांटेड आरोपी हैं। नक्सलियों के ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है। एनआईए ने झीरम घाटी हत्याकांड के वांटेड 19 आरोपियों की सूची तलाश जारी की है। आरोपियों पर 7 लाख से 50,000 हजार रुपये तक का इनाम घोषित है। वांटेड नक्सली या आरोपी की सूचना देने वाले को भी इनाम देने की घोषणा की है। आरोपियों की जानकारी मीडिया के माध्यम से जारी की गई है। बता दें कि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड में कांग्रेसी नेताओं समेत 32 लोगों की जान गई थी।

लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में होगी बहुत सारी टूटन : केदार

रायपुर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी मैराथन बैठक कर रही है। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और प्रभारी पर दावेदारों ने, विधायकों ने, प्रत्याशियों ने लगातार आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार में भ्रष्टाचार किया हैं, पार्टी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, लेन-देन की बातें सामने आ रही हैं, दुर्भाग्य है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में बहुत सारी टूटन होगी।

मीडिया से खास चर्चा में भाजपा द्वारा नए चेहरों के चयन को लेकर भूपेश बघेल के बयान पर केदार कश्यप ने पलटवार किया। सारे नेता हमारे लिए सम्मानीय है, और उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। बहुत सारे सीनियर नेता मंत्रिमंडल में हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, सत्यनारायण शर्मा, अमितेश शुक्ल का क्या हुआ। ऐसे कितने नेता हैं, जिनको दरकिनार किया। बीजेपी सबका सम्मान करती है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के

'बीजेपी सरकार आते ही बढ़ते नक्सली हमले पर' बयान पर केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि इसके संबंध में तो कवासी लखमा ही बता पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि उनके पास तो बहुत सारे सबूत हैं, और वह अपने जेब में लेकर चलते हैं। उस संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कवासी लखमा बता पाएंगे कि किस कारण से उन्होंने नक्सलियों को समर्थन दिया।

कांग्रेस द्वारा क्राउड फंडिंग किए जाने पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने आया है। लोगों ने उनको नकारा है। वह कोशिश कर रहे हैं कि फिर से अपने चेहरे को ठीक करें। वे आतंकवादियों और अपराधिक तत्वों के साथ खड़े होते हैं। जो इस प्रदेश को, इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ में खड़े दिखाई देते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे पर केदार कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय पदाधिकारी, सारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे नेता, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक थी, उसमें सम्मिलित हुए। हमारे बड़े नेताओं से भी मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हमारी केंद्र की सरकार पहले भी गंभीर थी। योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हुआ। जिन योजनाओं को बंद किया गया है, उन योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को प्राप्त हो, इस बात की चिंता मुख्यमंत्री को है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव के कांग्रेस के लोकसभा घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए जाने पर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भूपेश बघेल ने लगातार सार्वजनिक मंचों पर बुरा व्यवहार किया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ऐसे मंत्री, ऐसे डिप्टी सीएम, जिनको कलेक्टर तक न पूछे। केदार कश्यप ने कहा कि 2018 में यहां पर घोषणा पत्र लाया था, लेकिन 5 वर्षों में पूरा नहीं कर पाए। अब वह देश को ठगना चाहते हैं। देश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, इतने नासमझ नहीं हैं। 5 साल में पलट दिया। यह उदाहरण देश में देखने को मिलेगा। उन्होंने यहां पर घोषणा पत्र में संयोजक बनने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से मोहम्मद अकबर संयोजक बने थे।

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीया ने पूरे देश को अलर्ट किया है। मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश के कलेक्टरो से ऑनलाइन चर्चा की। अलर्ट किया है कि ऐसे मामले सामने हैं, तो उसे पर तत्काल काम किया जाए।

पीसीसी चीफ बैज ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

3100 में रूपये में धान खरीदी का नहीं लिया गया कोई निर्णय

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान चिंतित हैं। किसानों को समर्थन मूल्य पर ही भुगतान हो रहा है। 3100 रूपये में धान खरीदी का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किसानों को 3100रू कब और कैसे मिलेगी ?

दीपक बैज ने पत्र को लेकर कहा कि प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिख रहे हैं। क्योंकि धान खरीदी होते डेढ़ महीने से अधिक का वक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री का शपथ हो चुका है। शुक्रवार को मंत्री मंडल का गठन हुआ है। सिर्फ 21 किविंटल देने का स्वीकृति किया है। 31 क्विंटल धान देने का स्वीकृति नहीं किया है, जिससे किसान परेशान है। हमारी सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदना शुरू कर दिया था। हम चाहते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग कर रही है। कांग्रेस की ओर से पत्र जाना चाहिए। किसान लगातार आत्म हत्या कर रहे हैं, किसान परेशान न रहे।

राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया पिछले डेढ़ महीने से अधिक समय से शुरू है। किसान धान खरीदी केन्द्रों में अपना धान बेचने पहुंच रहे हैं लेकिन किसानों में दुविधा की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वायदे में किसानों से वायदा किया है कि वह धान की कीमत 3100रू प्रति क्विंटल देगी तथा इसका एकमुस्त भुगतान धान बेचने के तुरंत बाद खरीदी केन्द्रों की ग्राम पंचायतों में ही अलग से काउंटर बना कर किया जाएगा। इस संबंध में शासन के तरफ से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है और ना ही कोई निर्देश जारी हुआ है, जिसके कारण उनको समर्थन मूल्य पर ही भुगतान हो रहा है।

कांग्रेसियों को मनमुताबिक ट्रांसफर-पोस्टिंग न करा पाने का रंज है: श्रीवास्तव

रायपुर। कांग्रेस के लोग सत्ता में रहते हुए तो जनता से कटे-कटे रहे ही, अब जबकि प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका है तब भी अपनी हार की समीक्षा करते हुए भी जनता के प्रति अपने गैर-जिम्मेदाराना राजनीतिक आचरण को लेकर उन्हें कोई मलाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जनता के प्रति गैर-जवाबदेही और अपने सत्तावादी अहंकार के लिए सत्ता का बेजा इस्तेमाल ही कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र रहा है, यह कांग्रेस की समीक्षा बैठक से प्रमाणित हो रहा है।

श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री और सचिव की मौजूदगी में हुई कांग्रेस की बैठक में पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता एक-दूसरे पर पार्टी के साथ जमकर गद्दारी करने का आरोप लगा रहे हैं और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इसकी तस्दीक की है। आलम यह है कि कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, निगम-मंडल अध्यक्षों पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है। श्री श्रीवास्तव ने इस बात पर हैरत जताई कि कांग्रेस के लोगों का यह गुस्सा इस बात पर कतई नहीं है कि कांग्रेस की भूपेश सरकार के मंत्री, निगम-मंडल अध्यक्ष जनता के हित का काम नहीं किया, बल्कि यह गुस्सा इस बात का है कि कांग्रेस के शासनकाल में उनके मनमुताबिक अफसरों-कर्मियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह बताता है कि कांग्रेस जनता के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि अफसरों-कर्मचारियों पर सत्ता की धौंस दिखाकर रौब गालिब करने के लिए सत्ता हासिल करना चाहती है। पहले भी कांग्रेस ने यही किया, अपने पाँच साल के पिछले शासनकाल में भी यही किया। श्रीवास्तव ने कांग्रेस के इस आचरण पर करारा कटाक्ष कर कहा कि एक राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस का यह नजरिया बेहद शर्मनाक है।

वाजपेयी की जयंती 25 को मनाया जाएगा सुशासन दिवस

रायपुर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 की बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान किया जाएगा। धान उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना के लिए राशि का प्रावधान भी किया है। सुशासन दिवस के अवसर पर

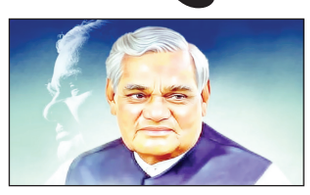

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम जनता की गरिमामय उपस्थिति में नगरीय निकायों में स्थापित अटल चौक में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। अटल चौक में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्जवलन कर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता द्वारा सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा 25 दिसंबर के पहले नगरीय निकायों में पूर्व से निर्मित अटल स्तंभ की साफ-सफाई, आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। यह स्वच्छता अभियान नगरीय निकायों में 25 दिसंबर से प्रारंभ होकर आगामी एक सप्ताह तक आयोजित होगा। सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल संध्या का आयोजन होगा। इसके अंतर्गत कवि सम्मेलन, अटल जी की कविता पाठ, अटल विचार संगोष्ठी, निबंध स्पर्धा का आयोजन तथा अटल जी के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर केन्द्रित प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।

अरुण साव ने महज 14 महीनों के कार्यकाल में भाजपा को पहुंचाया सत्ता के शिखर तक

रायपुर। विधानसभा चुनाव से महज 14 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ अध्यक्ष के तौर पर जब अरुण साव ने कमान संभाली थी, तब पार्टी कार्यकर्ता निराशा के गर्त में डूबे थे। लेकिन अल्प कार्यकाल में अरुण साव ने कार्यकर्ताओं में वह ऊर्जा भर दी, जिनकी मेहनत के बदौलत पार्टी 15 सीटों के अपने न्यूनतम स्तर से 54 सीटों के शिखर पर पहुंच गई। आज जब वे पार्टी अध्यक्ष का दायित्व सौंप चुके हैं, तब वे सीना फुलाकर गर्व के भाव से पीछे मुड़कर देख सकते हैं।

छत्तीसगढ़ गठन के बाद से प्रदेश भाजपा की कमान छह नेताओं ने संभाला है। पार्टी अध्यक्ष का दारोमदार सबसे पहले डॉ. रमन सिंह ने संभाला था। उनके नेतृत्व में 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज हुई थी। वहीं सत्ता पर काबिज कांग्रेस 37 सीटों पर जीत हासिल कर विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई थी।

डॉ. रमन सिंह के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी की कमान विष्णुदेव साय को मिली। साय के नेतृत्व में 2008 विधानसभा चुनाव में भाजपा

ने अपना प्रदर्शन दोहराते हुए फिर से 50 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन अबकी बार वोट प्रतिशत बढ़कर 39.26 से 40.33 प्रतिशत पर पहुंच गया।

विष्णुदेव साय के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान रामसेवक पैकरा को मिली। पैकरा के नेतृत्व में पार्टी ने 2013 का चुनाव लड़ा। इस बार पार्टी की सीट कम हुई, लेकिन वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। भाजपा को 49 सीटें मिली, वहीं वोट प्रतिशत 41.04 प्रतिशत पहुंच गया।

रामसेवक पैकरा के बाद पार्टी आलाकमान ने प्रदेश की जिम्मेदारी धरमलाल कौशिक को सौंपी। कौशिक के नेतृत्व में 2018 के चुनाव में उतरी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की सीटें एक झटके में 49 से घटकर 15 पर पहुंच गई। वोट प्रतिशत भी एक झटके में 41.04 से गिरकर 32.97 प्रतिशत पर पहुंच गया।

भाजपा के नेताओं-कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा समय था, जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में नहीं की थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आने वाले सालों में भी सत्ता पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए जनता को लुभाने के लिए तमाम काम कर रही थी।

निराशा के गर्त में डूबी पार्टी का नेतृत्व साहू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले अरुण साव को सौंपकर आलाकमान ने सबको चौंका दिया। लेकिन पार्टी की कमान सम्हालते ही अरुण साव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम शुरू किया। बिलासपुर की राजनीति से उठकर राजधानी की राजनीति में सामंजस्य बनाने के बाद दिल्ली का सफर शुरू किया।

महज 14 महीनों के अंतराल में अरुण साव ने राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर पार्टी को शिखर पर पहुंचा दिया। 2023 विधानसभा चुनाव में न केवल भाजपा को 54 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि वोट प्रतिशत को भी 46.27 प्रतिशत के ऐतिहासिक स्तर पर ले गए। आज पार्टी की कमान किरण सिंहदेव को सौंप चुके अरुण साव गर्व के भाव से पीछे मुड़कर देख सकते हैं।

वीर बाल दिवस का आयोजन 26 को प्रधानमंत्री के संदेश का होगा प्रसारण

रायपुर। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑडियो-विजुअल की स्क्रीनिंग के साथ ही वीर बाल दिवस पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस दौरान वीर बाल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। गौरतलब है कि वीर बाल दिवस श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों के सर्वोच्च बलिदान और साहस की स्मृति में मनाया जाता है।

छत्तीसगढ़ में वीर बाल दिवस को जोर शोर से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए सभी कलेक्टरों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वीर बाल दिवस के आयोजन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, पंचायत, उच्च शिक्षा और नगरीय प्रशासन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। गतिविधियों में एनवायके, एनएसएस, एनसीसी के वालेंटियर्स से मोबिलाईजेशन में सहयोग लेने भी कहा गया है। प्रदेश में वीर बाल दिवस के अवसर पर जिला स्तर, नगर पालिका, वार्ड, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं और किशोरों, देश वासियों, महिलाओं में राष्ट्रनिर्माण के लिए योगदान एवं मूल्यों को स्थापित करना और सुदृढ़ बनाना है। इसके लिए गतिविधियों में विशेषकर स्वतंत्रता सेनानियों एवं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत पूर्व विजेताओं के अनुभवों को साझा किया जाएगा।

सियासत के बाजीगर अब वो काम करेंगे जो अफसर रहते हुए नहीं कर पाए

रायपुर। आईएएस अफसर रहे ओ पी चौधरी अब मंत्री बन चुके हैं,छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर यदि बात करें तो स्व.अजीत जोगी के बाद चौधरी दूसरे ऐसे आइएएस होंगे जिन्होने राजनीति में अलग पहचान स्थापित की है। जैसे ही भाजपा में शामिल हुए खरसिया से टिकट मिल गई चुनाव लड़े और हार गए लेकिन मन से हार नहीं मानी और नए सिरे से डटकर राजनीति की बिसात पर आगे बढ़े पांच साल संगठन में जमकर काम किया,आम लोगों के बीच पहुंच बनाई,अब रायगढ से चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बन गए। हालांकि 13 साल का प्रशासनिक अनुभव रहा है लेकिन अब वे मान रहे हैं कि प्रशासनिक बंधनों से मुक्ति का अहसास कर रहे हैं। मंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ के लिए वह काम कर सकेंगे जो कि अफसर रहते हुए नहीं कर पाए।

चौधरी ने कहा कि वह चाणक्य के उस कथन से प्रभावित होकर राजनीति में आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने से पहला दुष्परिणाम ये होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करते हैं। इसलिए मैंने 13 साल के प्रशासनिक जीवन को छोड़ते हुए इस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और राजनीति में आया। उन्होंने कहा कि यह सच है कि आज राजनीति में अच्छे लोगों को आने की जरूरत है। हर कोई डाक्टर, इंजीनियर, वकील, आइएएस बनना चाहता है मगर लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 2 (छत्तीसगढ़)
ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

(प्रथम आमंत्रण)

दिनांक 19.12.2023

निम्नांकित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा "डी" श्रेणी एवं अधिक श्रेणी के ठेकेदारों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 08.01.2024 है।

एन.आई.टी क्र./ निविदा क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
NIT NO. 216 Tender No. 150192	बलौदाबाजार अनुविभाग अंतर्गत स्पोर्ट स्टेडियम बलौदाबाजार का निर्माण/रिनोवेशन का कार्य।	रू. 84.47 लाख
NIT NO. 217 Tender No. 150193	भाटापारा अनुविभाग अंतर्गत स्पोर्ट स्टेडियम भाटापारा का निर्माण/रिनोवेशन का कार्य।	रू. 37.72 लाख
NIT NO. 218 Tender No. 150194	जिला धमतरी के बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,धमतरी में अहाता (बाउण्ड्रीवाल) का निर्माण कार्य।	रू. 77.59 लाख
NIT NO. 219 Tender No. 150195	जिला महासमुन्द के उपसंभाग महासमुन्द क्रं.-1 अंतर्गत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पहुँच मार्ग लंबाई 0.500 किमी का निर्माण कार्य।	रू. 122.29 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट बेब पोर्टल **https://eproc.cgstate.gov.in** अथवा विभागीय वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। (राशि रू. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र एवं न्यूनतम राशि रू. 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम पर एनेक्जर-3 का शपथ पत्र ,बिडकेपेसीटी उपलब्धता बाबत् जानकारी एवं अन्य जानकारी एनआईटी के 2.10 में संलग्न संशोधित प्रपत्रानुसार प्रस्तुत करें।)

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

अधीक्षण अभियंता,
लो.नि.वि.,रायपुर मण्डल क्र. 2 (छ.ग.)

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

आपकी थी चाह, हमने बनाई राह

जी. 06635/7

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बीजापुर (छग)
(जल जीवन मिशन)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना (निविदा आमंत्रण सूचना)

जिला बीजापुर के विभिन्न विकासखण्डों के ग्रामों में नलजल प्रदाय योजना अन्तर्गत कार्य - पाईप लाईन एवं घरेलू नल कनेक्शन के लिए एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से नि नलिखित कार्य हेतु प्रपत्र ए में ऑनलाईन (Online) निविदा (प्रमुख अभियंता, लो.स्वा. यां. विभाग 01.06.2020 में Amedment date 01.07.2022 से प्रभावशील एवं निविदा रायपुर के यु.एस.ओ.आर. दिनांक छ.ग. जारी होने की तिथि तक समस्त संशोधन सहित दरों पर) आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ मिशन संचालक महोदय के निर्देशानुसार दिये नये ड्राफ्ट एन.आई.टी. में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के आधार पर आमंत्रित की जा रही है।

ठेकेदार निविदाएँ साईट में अपलोड नये ड्राफ्ट एन.आई.टी. के नियम एवं शर्तों के आधार पर ही निविदा में भाग लेवें पुराने नियम एवं शर्तों के आधार पर भाग लेने पर अपात्र कर दिया जावेगा। जिसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगें।

आमंत्रित निविदाएँ नि नानुसार है -

क्र	निविदा क्रमांक /तिथि	सिस्टम क्रमांक	ग्राम	कॉल	कार्य की अनु. लागत (रु.लाख में)	अमानत राशि राशि (रू. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	631/11.12.2023	149993	Chinnajojor	5th call	22.16	16620/-
2.	632/11.12.2023	149994	Dareli	5th call	61.56	46170/-
3	638/11.12.2023	149944	Sagmeta & Sallepalli	2th call	31.02	23265/-
4.	639/11.12.2023	149946	Dadhmer	2th call	26.55	19913/-
5.	640/11.12.2023	149947	Gunjakonta	2th call	17.97	13478/-
6	641/11.12.2023	149966	Badepalli	2th call	20.80	15600/-
7.	642/11.12.2023	149973	Adepalli	2th call	32.47	24353/-
8.	643/11.12.2023	149978	Fandiwaya & Cherpalli (Sandra) & Jaraguda	2th call	36.64	27480/-
9.	644/11.12.2023	149983	Mukram	2th call	11.42	8565/-
10.	652/11.12.2023	150055	Fulgundam	5th call	9.15	6863/-
11.	653/11.12.2023	150056	Pankudur	5th call	7.79	5843/-
12.	654/11.12.2023	150063	Marwada	5th call	8.11	6083/-

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की अंतिम तिथि दिनांक (Bid due date) 05.01.2024 तक आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ डाउनलोड करने की तिथि (Bid start date) 15.12.2023 से है। निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बीजापुर

जी. 06603/6

गजब बेचैनी है बिहार के राजनीतिक माहौल में

बिक्रम उपाध्याय

जब से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार के रुप में इंडिया गठबंधन की ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया है तभी से जनता दल यूनाइटेड में बेचैनी का माहौल है। मौजूदा 16 सांसदों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों के बीच अंदरखाने में अपने अपने भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हैं। सीतामढ़ी के जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने वनइंडिया से बातचीत में कहा कि केवल माननीय नीतीश कुमार ही जानते हैं कि जदयू का अगला रूख क्या होगा। क्या सभी 16 सांसदों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी है? इस पर जदयू सांसद पिंटू खुल कर नहीं बोलते, लेकिन सभी अपने अपने लिए नए खेमे की तलाश भी कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या अगला लोकसभा का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ने की योजना है, इस पर सुनील कुमार पिंटू हंसते हुए कहते हैं कि 2024 में देखा जाएगा। लेकिन सुनील कुमार पिंटू खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। वह राम मंदिर के बनाए जाने को विशुद्ध धार्मिक आस्था का विषय बताते हुए कहते हैं कि कुछ लोग तो राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे। वे कोर्ट में शपथ पत्र देकर कह रहे थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वे तो काल्पनिक हैं। सुनील कुमार पिंटू पिछले हफ्ते दिल्ली में नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, उस पर जेडीयू के नेता और बिहार के जलसंसाधन मंत्री संजय झा ने बयान दिया था कि सुनील कुमार पिंटू जदयू में है कहां? जेडीयू के बिहार के एक नेता का कहना है कि पटना में 29 दिसंबर को बुलाई गई बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। क्या पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदल सकती है? इस सवाल के जवाब में जदयू नेता का कहना है कि उनकी पार्टी में सर्वेसर्वा नीतीश कुमार ही हैं। वह जो भी निर्णय लेंगे, सब लोग उसे मानेंगे। उल्लेखनीय है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाए जाने की चर्चा जोरों से चल रही है। इस संबंध में पार्टी में कई अन्य नामों पर विचार भी कर रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जदयू से राज्य सभा के सांसद रामनाथ ठाकुर को कोई बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। कुछ लोग उन्हें ललन सिंह के विकल्प के रूप में भी देख रहे हैं। जदयू का पिछड़ा और अतिपिछडा वोट बैंक खिसकने की चिंता पार्टी के नेतृत्व को सता भी रही है। ललन सिंह जाति से भूमिहार हैं और उनका लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ करीबी रिश्ता होना भी पार्टी के नेताओं को अखर रहा है। इसलिए यह संभावना है कि जदयू अपने कोर वोट के लिए कोई बड़ा फेरबदल करे। ललन सिंह का पार्टी में भले ही विकल्प हो, लेकिन बिहार की राजनीति में पकड़ बनाए रखे और बिहार से केंद्र की राजनीति में धुरी बनने के विकल्प के रूप में उभरे नीतीश कुमार के लिए विकल्पों की कमी है। पार्टी में कोई भी बड़ा बदलाव या उथल पुथल अंततः नीतीश कुमार के लिए कमजोरी का कारण बनेगा। पार्टी के सांसदों को ही नहीं, विधायकों को भी अपने भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं हैं। इसलिए नेतृत्व को लेकर किसी बड़े संकट की स्थिति जदयू के विघटन का कारण बन सकती है। गाहे बगाहे जदयू के विधायक कोई न कोई अप्रिय बयानबाजी कर ही दे रहे हैं। इसलिए यह भी आशंका बन रही है कि कहीं जदयू विधायक दल में ही विभाजन ना हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद का परिवार फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। वे किसी भी राजनीतिक तूफान का कारण नहीं बनना चाहते। वे खामोशी से जेडीयू में हो रहे विवाद का नजारा देख रहे हैं। उन्हें सिर्फ आशंका इस बात की है कि कहीं नीतीश फिर से एनडीए में ना चले जाए। इसलिए अपनी ओर से राजनीतिक बयानबाजी से बच रहे हैं। एक संभावना यह भी है कि जदयू में नेतृत्व को लेकर यदि कोई बात आगे बिगड़ती है और पार्टी में कोई विभाजन की स्थिति बनती है, तो राजद अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर सकता है। जदयू में टूट की स्थिति में जो भी विधायकों को लेकर अलग होता है वह राजद के साथ सरकार में शामिल हो सकता है। जो भी हो बिहार की राजनीति में शीघ्र ही कुछ नया होने की परिस्थितियां बन रही हैं।

इंडिया के बैठकों का कुछ परिणाम निकलेगा

ललित गर्ग

संसदीय अवरोध, विपक्षी दलों के 143 सांसदों के निलम्बन एवं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने की घटनाओं से आक्रामक हुए राजनैतिक माहौल के बीच 28 पार्टियों का इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों के साथ चौथी बार फिर से दिल्ली में एक छत के नीचे आया। बैठक का उद्देश्य था कि विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग एवं संयोजक के नाम पर सहमति सहित कई मुद्दों पर एक राय कायम करना। लेकिन इंडिया गठबंधन की इस बैठक में दल भले ही आपस में मिले, लेकिन दिल नहीं मिल पाये। लोकतंत्र की मजबूती के लिये सशक्त विपक्ष बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्षी दलों की संकीर्ण सोच, सिद्धान्तविहीन राजनीति एवं सत्ता लालसा ने विपक्ष की राजनीति को नकारा कर दिया है। सोचा गया था कि इंडिया गठबंधन विपक्ष से जुड़ी लोकतांत्रिक भागीदारी की लौ को फिर से प्रज्ज्वलित कर सकेगा और ऐसी सोच एवं राजनीतिक प्रणाली का निर्माण करेगा जो वास्तव में लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए हो। लेकिन ऐसा न होना इंडिया गठबंधन की बड़ी असफलता है और आने वाले वर्ष 2024 के लोकसभा में उसकी भूमिका टांय-टांय फिस ही होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में एकजुटता की बातें हवा हो रही हैं। न संयोजक और न ही प्रधानमंत्री और न ही नरेन्द्र मोदी के सामने कौन चुनाव लड़े, के नाम पर सहमति बन पायी है।

आज दुनियाभर में लोकतंत्र विश्वास के संकट का सामना कर रहा है। भारत में विपक्ष की नकारात्मक स्थितियों के कारण यह संकट ज्यादा बढ़ा है। इसका कारण है विपक्ष से जुड़े संस्थानों, राजनीतिक हस्तियों और लोकतांत्रिक निर्णयों का आधार बनने वाली प्रणालियों पर धीरे-धीरे कम हो रहा भरोसा। विश्वास का यह संकट तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। आज हमें विपक्षी राजनीतिक तंत्र पर मौलिक विचार मंथन के बाद पुनर्मूल्यांकन कर इन्हें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बदलती हुई सामाजिक एवं राष्ट्रीय जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके और सरकार एवं शासन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकें जिसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं का नहीं बल्कि नागरिकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का महत्त्व हो।

इंडिया गठबंधन की प्रथम अपेक्षा है कि इससे जुड़े सभी दलों में आपसी सहमति एवं एकजुटता बने। लेकिन चौथी बैठक में ऐसा होता हुई नहीं दिखा। सबसे खास बिहार के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम सहमति बनाने की अपील की, लेकिन जिस बात का डर शुरू से था वही हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया, जिससे विपक्षी एकजुटता में सेंध लगी और राजनीतिक माहौल गरमा गया। ममता दीदी ने चाल चलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री/संयोजक पद के लिए रख दिया जबकि इस नाम के लिए नीतीश प्रारंभ से लामबंदी कर रहे थे। खड़गे का नाम सुनते ही ना सिर्फ नीतीश बल्कि नीतीश के नाम के पीछे अपने बेटे तेजस्वी का भविष्य तलाशने वाले लालू यादव भी नाराज हो गए। नाराजगी ऐसी कि दोनों दिग्गज लालू और नीतीश कुमार गठबंधन की बैठक के बीच से ही निकल गए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या गठबंधन में सिर्फ बैठकें होंगी या फिर कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। क्या गठबंधन लोकसभा चुनाव की कोई प्रभावी एवं सार्थक चुनावी प्रक्रिया तय कर पायेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। मोदी के रथ पर सवार बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन ऐड़ी चोटी का जोड़ तो लगा रही है, लेकिन सभी दल एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन कोरा सत्ता के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन लोकतांत्रिक आदर्श के लिए नहीं। ऐसा माना जाता है कि सत्ता समझौतों पर टिकी होती है और आदर्श सिद्धांतों पर। दोनों में संतुलन और सामंजस्य की स्थितियां दुर्लभ होती जा रही हैं। विपक्षी दल चाहे कितनी ही समस्याएं पैदा करते हों, लेकिन अगर वे अलग-अलग मुद्दों से ज्यादा नीतिगत प्रश्नों पर ध्यान दें तो उन्हीं के जरिए लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। कोई भी दल सत्ता में आने के लिए गठबंधन तब करता है जब अकेले सरकार बनाने या जीतने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन आदर्शवादी राजनीतिक सोच इसे सत्तामोह और समझौतावाद कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सिद्धांतवादी दलों को किसी से गठजोड़ नहीं करना चाहिए, भले उसका परिणाम राजनीतिक असफलता ही क्यों न हो। लेकिन राजनीति में गठबंधन एक विवशता बनती जा रही है, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल में सिद्धान्त एवं मूल्यों की राजनीति करने का माद्दा नहीं उभर पा रहा है।

इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की ताकत बनना चाहिए क्योंकि इसने एकदलीय सत्ता का युग खत्म होने के बाद राजनीतिक अस्थिरता और खर्चीले चुनावों के खतरे के प्रति सचेत होकर गठबंधन की सीख बहुत जल्दी ले ली। लेकिन गठबंधन की बुनियादी सोच को विकसित किये बिना ऐसा करना जल्दबाजी एवं सत्ता मोह का निर्णय ही अधिक प्रतीत हो रहा है जिसका कोई सार्थक परिणाम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही विपक्षी दल सिद्धांत और विचारधारा के बदले आर्थिक विकास और व्यापार-रोजगार जैसे नारों से लोगों को लुभा लें। लेकिन ऐसा करते हुए वे अवसरवाद की पुष्टि और विचारधारा के अवमूल्यन के लिए उदाहरण ही प्रस्तुत करते हैं। ऐसे दलों के नेताओं का चरित्र एवं साख भी कोई प्रभावी रंग नहीं दिखा पाती। वे एक दल से दूसरे दल में बेहिचक आते-जाते हैं, पितृदल छोड़ कर नए-नए दल बनाते हैं। यह सब राजनीतिक विचारधारा के अंत का सूचक है।

यह देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति में सिद्धांतों और मूल्यों की बातें मजाक होकर रह गई हैं। बड़ी सोच एवं बड़ी दृष्टि इन विपक्षी दलों में पनप ही नहीं पा रही है। इंडिया गठबंधन में कुछ संभावना बनी थी, लेकिन उसमें भी न तो बड़ी दृष्टि है न देश की सही समझ और न ही बड़ी लड़ाई लड़ने का दम और जीवट दिखाई पड़ता है। अगर वाकई देश को राजनीतिक विनाश के रास्ते से हटा कर सही एवं सकारात्मक रास्ते पर लाना है तो जीवट नेतृत्व की अपेक्षा है। ऐसा विपक्षी नेतृत्व उभरे जिसमें समझ और तप दोनों का समावेश हो। राष्ट्र एवं समाज को विनम्र करने का हथियार मुद्दे या लॉबी नहीं, पद या शोभा नहीं, ईमानदारी है। और यह सब प्राप्त करने के लिए ईमानदारी के साथ सौदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि राष्ट्र, सरकार, समाज, संस्था व संविधान ईमानदारी से चलते हैं, न कि झूठे दिखावे, आश्वासन एवं वायदों से। दायित्व और उसकी ईमानदारी से निर्वाह करने की अनभिज्ञता संसार में जितनी क्रूर है, उतनी क्रूर मृत्यु भी नहीं होती। मनुष्य हर स्थिति में मनुष्य रहे। अच्छी स्थिति में मनुष्य मनुष्य रहे और बुरी स्थिति में वह मनुष्य नहीं रहे, यह मनुष्यता नहीं, परिस्थिति की गुलामी है।

हमारा विपक्षी नेतृत्व अपने पद की श्रेष्ठता और दायित्व की ईमानदारी को व्यक्तिगत अहम् से ऊपर समझने की प्रवृत्ति को विकसित कर मर्यादित व्यवहार करना सीखें अन्यथा शतरंज की इस बिसात में यदि प्यादा वज़ीर को पीट ले तो आश्चर्य नहीं। बहुत से लोग काफी समय तक दवा के स्थान पर बीमारी ढोना पसन्द करते हैं पर क्या वे जीते जी नष्ट नहीं हो जाते? खीर को ठण्डा करके खाने की बात समझ में आती है पर बासी होने तक ठण्डी करने का क्या अर्थ रह जाता है? लोगों के दिलों को जीतने की राजनीति ही सार्थक परिणाम लाती है, विपक्षी दल यह बात भूल कर कब तक अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। विपक्षी दलों को लोगों के विश्वास का उपभोक्ता नहीं अपितु संरक्षक बनना होगा। भारत न केवल अपने आकार के कारण, बल्कि तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलन और पनपने की अपनी क्षमता के कारण दुनिया की एक महाशक्ति बन रहा है, इन बदलती स्थितियों में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती देने के लिये विपक्षी दलों को एक आदर्श मॉडल के रूप में अपनी सहभागिता देनी चाहिए।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामण्युपनिषद् (भाग-20)

गतांक से आगे...

दोनों पैर की एड़ियों को मेढ्र अर्थात् सीवन स्थान में लगाकर आसन में दृढ़तापूर्वक बैठे, तत्पश्चात् आँख, कान एवं नाक को अँगुलियों से बन्द करे और मुँह से वायु खींचे। पुनः नीचे से अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाए, फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश में रोके। पुनः ऊर्ध्वगामी बनाकर मस्तिष्क में स्थिर करके मन को उसी में लगाए, इस क्रिया से योगियों को विशेष समत्वभाव प्राप्त होता है।

ऊपर और नीचे दोनों ओर से गतिशील वायु जब आकाशमण्डल (हृदय प्रदेश) में स्थिर होती है, तब साधक को महान् ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, घण्टा आदि वाद्यों की तरह ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा नादयोग की सिद्धि होती है। विधिवत् प्राणायाम के अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। प्राणायाम के न करने से यह शरीर रोगों का उत्पत्तिस्थान बना रहता है। वायु के विकृत होने के कारण ही खाँसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आँख की पीड़ा होती है और नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि हिंस्र पशु जिस प्रकार से धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा वश में होते हैं, उसी तरह प्राणवायु को शनैः-शनैः अभ्यास के द्वारा वश में करे। यदि साधक ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसका विनाश हो जाता है। समुचित तरीके से प्राणवायु को खींचे, समुचित तरीके से प्राणवायु को बाहर निकाले तथा समुचित तरीके से ही प्राणवायु को रोकने से सिद्धि प्राप्त होती है। आँख आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों की ओर भागती हैं, उनको वहाँ से रोकना (और इष्ट साधना में लगाना) प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे-जैसे तृतीय प्रहर (सायंकाल) होता जाता है, वैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को समेटता जाता है और सायंकाल को पूरी तरह समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार योगी अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हुए (तीन अवस्था, तीन गुण, तीन शरीर से आगे बढ़ते हुए) जब अपने तृतीयांग (उच्च योग के तृतीयांग समाधि) में स्थित हो जाता है, तो वह अपने मन के समस्त विकारों का शमन कर लेता है। यही उपनिषद् (रहस्य विद्या) है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

ललित गर्ग

उपभोक्ता में उत्पादकता और गुणवत्ता संबंधित जागरूकता को बढ़ाने, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल इत्यादि संकटों से उपभोक्ता को मुक्ति दिलाने एवं उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए इसी दिन 24 दिसंबर, 1986 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 लागू किया गया था। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। यह दिन भारतीय ग्राहक आन्दोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया और आगे भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण कानून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है की किसी भी शासकीय पक्ष ने इस विधेयक को तैयार नहीं किया बल्कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रथमतः इस विधेयक का मसौदा तैयार किया। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान खरीदता है, वह उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं हैं इसलिए हर जगह ठगा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को जागना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना होगा। बहुत कम उपभोक्ता जानते होंगे कि उनके क्या अधिकार हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसलिये मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और इसके साथ ही अगर वह धोकाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली आदि का शिकार होते हैं तो वह इसकी शिकायत कर सकें। इस कानून में जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं की बिक्री के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो के बारे में जानकारी का अधिकार एवं इसके लिए आवाज उठाने का अधिकार है। उपभोक्ता दिवस मनाते हुए हम केवल उपभोक्ता अधिकारों की ही बात नहीं करते बल्कि उपभोक्ता की उन्नत एवं सम्यक् सोच को भी विकसित करते हैं। फ्रांसीसी विचारक विचारक ज्यां बोद्रियो ने आधुनिक उपभोक्तावाद की मीमांसा करते हुए कहा है कि पहले वस्तु आती है तो वह सुख देने वाली लगती है।

पाकिस्तान के कर्मों ने ही तालिबान को बना दिया दुश्मन

मनीष राय

हाल ही में एक नाटकीय खुलासा हुआ कि कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख और तालिबान की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था और उसे रद्द कर दिया गया है। यह घटनाक्रम थोड़ा अजीब था क्योंकि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान का पुराना सहयोगी माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय देखने में आया है की पाकिस्तान और उसके चहेते हक्कानी नेटवर्क के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान की अफगान नीतियों की आलोचना की जैसे- उन्होंने अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निष्कासित करने के पाकिस्तान सरकार के फैसले को गैरइस्लामिक बताया। कई विश्लेषकों का मानना है कि हक्कानी का पाकिस्तानी पासपोर्ट रद्द कर के तालिबान शासन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गयी। पिछले महीने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि आसिफ दुर्रानी ने अपनी चेतावनी दोहराते हुए कहा था कि अफगानों को पाकिस्तान या टीटीपी को चुनना होगा। पिछले कुछ समय से इस्लामाबाद और काबुल के बीच तापमान बढ़ रहा है। टीटीपी पर लगाम लगाने से इंकार करके, पाकिस्तान का मानना है कि मौजूदा अफगान शासन ने पहले ही अपनी पसंद बना ली है। और अब इस्लामाबाद पाकिस्तान से लाखों अफगान शरणार्थियों को बाहर निकाल कर, प्रमुख सीमा मार्ग बंद करके और हाल के महीनों में अफगान पारगमन माल को अस्थायी रूप से रोककर अफगान तालिबान को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। अफ़ग़ान-पाक क्षेत्र पर नज़र रखने वाले कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध, जो दशकों से करीबी सहयोगी के रहे हैं, संकट के बिंदु पर पहुंच गए हैं तनाव के और बढ़ने से दोनों देशों के सुरक्षा और आर्थिक हितों को नुकसान हो सकता है।

वर्तमान में, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच विवाद का मुख्य कारण तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) है जिसे पाकिस्तानी तालिबान के नाम से अधिक जाना जाता है, लेकिन अन्य कारण भी हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को खराब करने में योगदान दे रहे हैं। आइए इन पर एक नजर डालें।

गहरा अविश्वास- तालिबान पाकिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में काम करना या दिखना भी नहीं चाहता। उन्हें अब पाकिस्तानी सरकार विशेषकर उसके सैन्य प्रतिष्ठान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिकी दबाव के कारण वह जल्द ही दुश्मन बन गया और तालिबान नेताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपने की हद तक चला गया। पाकिस्तान के इस विश्वासघात को तालिबान ने हमेशा याद रखा और नाराजगी जताई। जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में थीं, तब तालिबान ने राजनीतिक सुविधा और पनाहगाहों की आवश्यकता के कारण पाकिस्तान के साथ संबंध बहाल किए और बनाए रखे। लेकिन अब पनाहगाहों की जरूरत नहीं है, इसलिए तालिबान को अपने अस्तित्व के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है।

सीमा विवाद- पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव का एक और महत्वपूर्ण कारण अफ-पाक सीमा है जिसे आमतौर पर डूरंड रेखा के रूप में जाना जाता है। तालिबान, सभी पूर्ववर्ती अफगान सरकारों की तरह, डूरंड रेखा को दोनों देशों के बीच की सीमा के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में, पाकिस्तानी सेना और तालिबान बलों के बीच सीमा पर झड़पों की एक श्रृंखला हुई है, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने शुरू में कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था।

पाकिस्तान द्वारा शांति वार्ता का शोषण- पाकिस्तानी सेना के अनुरोध पर अफगान तालिबान ने टीटीपी और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया और काबुल में शांति वार्ता की मेजबानी की। हालाँकि, टीटीपी के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने जो दोहरी भूमिका निभाई, उससे अफगान तालिबान नाराज हो गया। पाकिस्तान ने टीटीपी के वरिष्ठ कमांडरों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए बातचीत का इस्तेमाल एक जाल के रूप में किया और अफगानिस्तान के अंदर उनमें से कई को निशाना बना के मारा गया।

पाकिस्तान का आर्थिक ब्लैकमेल- पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि अफगानिस्तान आर्थिक रूप से उस पर निर्भर रहे। अफ़ग़ानिस्तान एक ज़मीन से घिरा देश है और इसका अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के माध्यम से होता है। अफ़गानों की इस निर्भरता को पाकिस्तान पहले भी कई बार ब्लैकमेलिंग और दबाव बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर चुका है। हाल ही में पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान जाने वाले आयात से भरे हजारों कंटेनरों के पारगमन को अस्थायी रूप से रोक दिया था, जो महीनों से कराची के बंदरगाह शहर में फंसे हुए थे। वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग खोलने के लिए तालिबान ने देश के दक्षिण-पूर्व में स्थित ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह तक पहुंच के लिए ईरानियों से संपर्क किया है।

रणनीतिक विविधता- तालिबान शासन क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रमुख शक्तियों के साथ कामकाजी संबंध स्थापित करके अपने भूराजनीतिक पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहता है। यही कारण है कि तालिबान ने पारंपरिक रूप से अपेक्षाकृत मधुर भारत-अफगानिस्तान संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश की है। तालिबान अधिकारियों (जिनमें कभी भारतीय ठिकानों पर हमलों में शामिल लोग भी शामिल थे) ने भारतीय कंपनियों से रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है, जिस पर नई दिल्ली सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इससे पाकिस्तानी नीति निर्माताओं में चिंता बढ़ रही है।

काबुल में अत्यधिक निर्भर सरकार बनाने का इस्लामाबाद का दीर्घकालिक उद्देश्य अब अंततः धराशायी हो गया है। जैसा कि वर्तमान में सत्तारुढ़ तालिबान शासन के साथ है, जो पाकिस्तान को कोई रणनीतिक लाभ प्रदान करने या सुरक्षा में योगदान देने के बजाय, इस्लामाबाद के लिए एक चिंताजनक राह का कांटा बन गया है। अफगान तालिबान को मजबूर करने के लिए पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को बाहर निकालने जैसे एकतरफा फैसले ले रहा है, लेकिन इन कदमों से काबुल में पाकिस्तान के लिए अभी भी बची हुई थोड़ी-सी राजनयिक सद्भावना खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर, यह अफगानिस्तान में पहले से ही व्याप्त पाकिस्तान विरोधी जनमत को और भी प्रबल करेगा। इस्लामाबाद में नीति निर्माताओं को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी अफगान नीति बुरी तरह विफल रही है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

आज का इतिहास

1798 रूस और ब्रिटेन द्वितीय विरोधी फ्रांसीसी गठबंधन पर हस्ताक्षर किये गए।
1818 जोसेफमोहर और फ्रांज ग्रुबर की क्रिसमस कैरोल की मूक नाइट (ऑडियो विशेषताओं) को पहली बार ऑस्ट्रिया के एक चर्च में प्रदर्शित किया गया था।
1865 अमेरिकी गृहयुद्ध के छह कंफेडरेट दिग्गजों ने कू क्लक्स क्लान की स्थापना की, जो बाद में एक सफेद वर्चस्ववादी समूह बन जाएगा।
1913 अमेरिका के मिशिगन के कैलमेट में एक भीड़ भरी क्रिसमस पार्टी में भगदड़ मचाने के बाद भगदड़ मचने से सत्तर लोगों की मौत हो गई।
1914 ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने क्रिसमस मनाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध को बाधित किया, जिससे क्रिसमस की शुरुआत हुई।
1924 लंदन के क्रॉयडन एयर फील्ड में एक विमान दुर्घटना में 8 लोग मारे गए।
1936 पहली बार जॉन लॉरेन्स ने रेडियोएक्टिव आईसोटोप दवाई का प्रयोग मरीज पर किया।
1953 न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पर, तांगिवई में, एक रेलवे पुल एक लहार से क्षतिग्रस्त हो गया और एक यात्री ट्रेन के नीचे गिर गया, जिसमें 151 लोग मारे गए।
1954 लाओस को फ्रांस ने आजाद किया।
1964 साइगॉन में ब्रिन्ड्स होटल में बमबारी हुई।
1968 नासा अपोलो 8 मिशन के अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स, चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए पहली बार यात्रा की, ने प्रसिद्ध तस्वीर अर्थराइज (चित्र) ली, जिसमें पृथ्वी को चंद्र सतह से ऊपर उठते दिखाया गया।
1971 पेरू एयरलाइंस एयरलाइंस इलेक्ट्रा अमेज़ॅन के हेडवाटर पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, 10 दिनों के बाद जूलियन मार्गरिट कोपेके को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है।
1973 मोहम्मद मोहम्मदुल्ला बांग्लादेश के कार्यवाहक अध्यक्ष बने।
1973 यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने वाशिंगटन, डीसी के गृह शासन को मंजूरी दे दी, जिससे निवासियों को अपने मेयर और नगर परिषद का चुनाव करने की अनुमति मिली।
1979 पहला यूरोपीय एरियन रॉकेट लॉन्च किया गया।
1979 सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। यह हमला 1978 के सोवियत अफगान मैत्री संधि के बहाने किया गया था।

अपनी जड़ों की ओर लौटता श्रीराम का देश

गिरीश पंकज

श्रीराम केवल एक शब्द नहीं है, यह भारतीय अस्मिता और आस्था का प्रतीक भी है। श्रीराम केवल राजा ही नहीं हैं, वे वंचितों और हाशिये पर खड़े व्यक्ति को गले लगाने वाले अप्रतिम नायक भी हैं। लेकिन जो राम में जो रमा, वही उसके महत्व को समझ सका। भारतीय मनीषा ने सदियों पहले आराध्य राम के मूल्य को समझा था और राम को अपने जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बनाकर जीने की प्रविधि विकसित की थी। अनेक धार्मिक ग्रंथों में रामजी की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस की रचना करके प्रभु श्री राम को घर-घर पहुँचा दिया। महर्षि वाल्मीकि की कृति रामायण संस्कृत में थी इसलिए बहुत से लोग सैकड़ो साल पहले उसका ठीक से अवगाहन नहीं कर पाते थे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय की खड़ी बोली जनभाषा अवधि में रामचरितमानस की रचना की।

उन्होंने रामलीला के मंचन की शुरुआत भी की। उसका शुभ परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे पूरे देश में रामलीलाओं का मंचन होना शुरू हुआ और घर-घर में रामायण का पठन-पाठन शुरू हो गया।हमारे गिरमिटिया मजदूर आज से डेढ़ सौ साल पहले मजदूर बना कर सूरीनाम,गयाना, मॉरीशस और त्रिनिदाद आदि देशों में ले जाए गए, तो वे सब भगवान श्रीराम के सहारे ही वहाँ गए। उनके साथ रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी कृतियां थीं। हमारे मजदूर भाई उसे वक्त बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे लेकिन इतना तो था कि वे मानस और चालीसा को पढ़ सकते थेम उसी के सहारे उन्होंने बर्बर यातनाएं सहते हुए उन देशों को हरा- भरा किया और आज उनकी सुशिक्षित संतानें वहां राज कर रही हैं। तो यह राम का प्रताप ही है, जो सात समंदर पार भी अब तक फल-फूल रहा है। दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि वह मुगलों का गुलाम बना और इस दौर में हमारे अनेक मंदिरों को नष्ट किया गया।

राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई । यह बाबर के काल में हुआ। उस समय विरोध करने का मतलब था अपनी जान गंवा देना। अनेक हिंदुओं ने जान गंवाई भी। और जो बेचारे कमजोर लोग थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म भी अपना लिया । आज देश में जितने भी मुसलमान हैं, वे सब अपने समय में हिंदू ही थेम अनेक मुस्लिम बंधु इस सत्य को स्वीकारते भी हैंम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कभी कहा था कि इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है । यह राष्ट्र तो शुरू से सनातन रहा है ।मुगलों के आक्रमण के पहले यह देश हिंदू राष्ट्र ही था। यह अलग बात है कि यहां वर्ण व्यवस्था थी । ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र (यानी शुद्ध) जैसी सामाजिक व्यवस्था थी और सबका समान महत्व था। मुगलों के आने के बाद उनके वंश यहां बढ़ता गया क्योंकि अनेक हिंदुओं ने धर्मांतरण कर लिया था। देखते-ही-देखते अब वे एक बड़ी संख्या में देश के नागरिक हैं।

दु:खद बात यह है कि उनमें से कुछ लोग इस भारत भूमि के प्रति अपनी आस्था नहीं रखते। उनको केवल अपना धर्म से प्यार है। (यह विमर्श का एक अलग मुद्दा है जिस पर फिर कभी बात होगी और होनी भी चाहिए) बहरहाल, मैं भगवान श्री राम की ओर लौटता हूँ, जिनके संपूर्ण चरित्र ने सनातन-संस्कृति को बहुत हद तक प्रभावित किया। और इसमें दो राय नहीं कि रामचरितमानस के माध्यम से राम का जो चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, उसने हमारे सांस्कृतिक वैभव को द्विगुणित कर दिया। रामायण के तमाम सकारात्मक पात्र हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। श्रीराम, माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ल, दशरथ, माता कौशल्या, हनुमान, विभीषण, जटायु आदि सारे पात्र अपनी विशेषताओं के कारण समाज में न केवल पूजनीय पात्र हैं वरन उनके जीवन को देखकर हम निरंतर प्रेरित भी होते हैं ।रामचरितमानस के खल पात्र भी हमें यह संदेश देते हैं कि हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे भव्य चरित्र श्रीराम काम ऐसे भगवान राम के मंदिर को नष्ट करके जब अयोध्या में मस्जिद बनाई गई तो यह पूरे देश के लिए दुखद घटना थी। लेकिन आखिर कब तक सनातन समाज चुप रहता? आखिरकार वह विवादित ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। उसे लेकर एक तथाकथित उदारवादी वर्ग छाती भी पीटता रहा, लेकिन जो होना था, वह तो हो ही गया।अब वहां एक भव्य मंदिर बन गया। यह भी कितनी विचित्र बात है कि इस देश के बहुसंख्यक हिन्दू समाज को अपने आराध्य की जन्मभूमि के लिए पाँच सौ साल तक का इंतजार करना पड़ा। पूरी दुनिया में यह अपने किस्म का अद्भुत उदाहरण है कि अपनी ही जमीन को प्राप्त करने के लिए इस देश के लोगों ने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी।

लेकिन अंत भला तो सब भला। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया। फैसला देना ही पड़ता, क्योंकि राम जन्मभूमि में बनी मस्जिद अवैध थीम वह मंदिर तोड़कर बनाई गई थी । आज भी जब

मंदिर वहीं बनाया है...

जहां लिया अवतार राम ने,
मंदिर वहीं बनाया है।
देख भव्यता पुण्यधाम की,
जन-गण-मन हर्षाया है।।

रामकाज को करने वाले,पीछे कब रह पाते हैं ।
करके वे बलिदान स्वयं का,इक इतिहास बनाते हैं ।
हर युग में सब प्रभुभक्तों ने,जोखिम सदा उठाया है।।
जहां लिया अवतार राम ने,
मंदिर वहीं बनाया है।।

सदियों पहले पुण्य धरा पर,चंद विधर्मी आए थे।
नष्ट हमारा वैभव करके,दुख सबको पहुँचाए थे।
दूर हुआ अब दुख सदियोंका,नव इतिहास रचाया है।।
जहां लिया अवतार राम ने,
मंदिर वहीं बनाया है।।

विश्वगुरु इस भरत भूमि को,हमें बचा कर रखना है।
सदगुण का उद्यान राष्ट्र यह,इसे सजा कर रखना है।
वीर सुतोंके पुण्य ने इसको, शिखर तलक पहुंचाया है।।
जहां लिया अवतार राम ने,
मंदिर वहीं बनाया है।।

सियाराम ये नाम न केवल,इसमें रमना है हमको ।
इनके पथचिन्हों पर चलके,जीवन गढ़ना है सबको।
लखन-शत्रुघ्न और भरत ने,पथ सुंदर दिखलाया है।।
जहां लिया अवतार राम ने,
मंदिर वहीं बनाया है।।

हम काशी विश्वनाथ मंदिर को देखने जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि मंदिर को नष्ट करके वहां मस्जिद खड़ी की गई । इसी तरह जब हम मथुरा जाकर कृष्ण जन्मभूमि को देखते हैं, तो भी समझ में आ जाता है कि वहां खड़ी मस्जिद के पीछे क्या कहानी थी। इसलिए अगर काशी और मथुरा को लेकर भी हिंदू समाज कानूनी लड़ाई लड़ रहा है तो हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल सर्वोच्च न्यायालय की ओर से नियोजित फैसला होगा ।

भगवान श्री राम के मामले में राजनीति खूब हुई जबकि श्री राम राजनीति का नहीं, आस्था का विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खैर श्रीराम का नाम के नाम का सहारा लेकर सकारात्मक राजनीति करती रही, लेकिन विपक्ष के लोग तो राम के अस्तित्व को ही नकारते रहे। मगर जब उनकी नैया डांवाडोल होने लगी तो उन्होंने भी राम का नाम लेना शुरू किया। मंदिरों में जाकर माथा टेकने का पाखंड भी कांग्रेसियों ने करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा सरकार 2003 में आई, तो उन्होंने राम वन गमन मार्ग के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी वर्षों तक छत्तीसगढ़ के वनों में विचरते रहे।

भाजपा ने राम वनगमन पथ को चिन्हांकित किया और उस दिशा में कार्य भी शुरू कर दिया था। पन्द्रह साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने भी महसूस किया कि राम के बगैर उनका उद्धार नहीं हो सकता। अगर जनता के बीच अपनी छवि बनानी है तो राम के काम को करना ही होगा इसलिए उन्होंने भी इस दिशा में कार्य करना शुरू किया और राम वन गमन मार्ग को विकसित करने की दिशा में कुछ काम शुरू कर दिया था। भगवान श्री राम की माता कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। चंदखुरी नामक क्षेत्र में । वहां माता कौशल्या के मंदिर को कांग्रेस के शासनकाल में और सुंदर बनाया गया। वहां राम भगवान की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई। (हालांकि वह मूर्ति शिल्प की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमे सुधार ज़रूरी है।) चंदखुरी का मंदिर बहुत प्राचीन है, जिसे भाजपा सरकार ने थोड़ा- बहुत ठीक करने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के आने के बाद इसे और बेहतर किया गया। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार वापस लौटी है तो उम्मीद की जाती है कि राम वनगमन पथ पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाएगा और जहां-जहां राम के चरण पड़े, वहां-वहां भव्य पर्यटन स्थल भी बनाया जाएगा। ऐसा होने से छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास भी होगा। आज अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है तो जाहिर है कि पूरी दुनिया के लोग उस मंदिर को देखने आएंगे और उसका लाभ अयोध्या नगरी को मिलेगा। वहां के लोगों का आर्थिक विकास होगा। इस पैटर्न पर छत्तीसगढ़ में भी काम होना चाहिए। चंदखुरी के कौशल्या मंदिर को और भव्य बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। एक सुझाव यहां यह भी हो सकता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसका छोटा रूप चंदखुरी में भी बनाया जा सकता है । ऐसा होने से वह क्षेत्र और अधिक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा।

भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ में रहते हुए अनेक राक्षसों का संहार किया था, ऐसे स्थान आज भी सरगुजा और बस्तर में चिन्हांकित किए गए हैं। वहां भी भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात की ध्यान रहे कि श्री राम, सीता, हनुमान ये सब केवल आराधना के केंद्र नहीं हैं, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाले सुंदर पाठ भी हैं। इनके जीवन को हम अपने जीवन में रूपांतरित करके अपने अंतर्मन में उनकी छवि स्थापित कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सके तो इस देश में रामराज को आने से कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ की धर्मप्राण जनता आज भी राम के बिना नहीं रह सकती। अनेक लोग जब आपस में मिलते हैं तो अभिवादन में राम-राम ही कहते हैं। छत्तीसगढ़ में एक समुदाय तो ऐसा है जिसे रामरमिहा संप्रदाय ही कहते हैं ।ये ऐसे अनोखे रामभक्त हैं, जिन्होंने अपने शरीर के हर हिस्से पर राम नाम को गुदवा कर रखा है। सिर से लेकर पैर तक । प्रणम्य लोग हैं, जिन्होंने अपने तन पर राम का नाम गुदवाया ही नहीं, राम की सादगी भी आत्मसात की है। पूरे समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहरहाल बदली ही परिस्थिति में जब पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद राममय होता जा रहा है, तब छत्तीसगढ़ में भी अतिउत्साह है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में छत्तीसगढ़ की भी मिट्टी वहां पहुंची । यहां के अनेक लोगों ने वहां जाकर श्रमदान भी किया। और शायद इसी का नतीजा है कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे का जयघोष करने वालों को एक बार फिर छत्तीसगढ़ में शासन करने का अवसर मिल गया है। इसमें दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस देश में सनातन संस्कृति को लेकर एक विमर्श शुरू हो गया है। हम कह सकते हैं कि यह देश अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है । कुछ लोग सनातन को गाली दे रहे हैं लेकिन ऐसा करके वे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी वापसी की है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इन राज्यों में निवास करने वाले लोगों की सनातन के प्रति बढ़ती हुई आस्था ही है। छत्तीसगढ़ की एक दो विधानसभाओं में मतदाताओं में उनका सनातन बोध स्पष्ट रूप से दिखा।

कांग्रेस की हार के लिए सिर्फ क्षेत्रीय नेता जिम्मेदार!

अंजन कुमार चौधरी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शायद बड़ी आसानी से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी की करारी हार का ठीकरा स्थानीय नेताओं पर फोड़कर बच निकलने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जबकि, तीनों उत्तर भारतीय राज्यों में जो भी चुनाव परिणाम आया, उसके लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और खुद राहुल गांधी भी जिम्मेदारी लेने से बच नहीं सकते। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां पार्टी अपनी शानदार जीत पक्की मानकर ही मैदान में उतरी हुई थी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गुरुवार को राहुल गांधी ने तीनों राज्यों में हार का ठीकरा सीधे क्षेत्रीय नेताओं पर फोड़ दिया। उन्हें लग रहा है कि सहयोगी दलों (इंडिया ब्लॉक) को दरकिनार करने से ही हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की मिट्टी पलीद हुई है। राहुल ने बैठक में कांग्रेस नेताओं से कथित तौर पर कहा है कि पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपना वोट शेयर बनाए रखने में सफल रही है, लेकिन दूसरों का वोट खिसकने से बीजेपी का वोट शेयर बहुत बढ़ गया है। अब उनके मन में सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस वैसे वोट जुटाने में क्यों नाकाम रही? सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी के सामने इसके लिए तेलंगाना का उदाहरण भी रखा, जहां कांग्रेस करीब एक साल में 20% वोट शेयर जुटाने में कामयाब हुई है। उनके हवाले से एक नेता का कहना था कि तीनों राज्यों के क्षेत्रीय नेता नए लोगों को जगह देने के विचार के खिलाफ थे। सीडब्ल्यूसी में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत कई और नेताओं ने भी एमपी में हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की आलोचना की। क्योंकि, उनके मुताबिक वही समाजवादी पार्टी को सीट देने को तैयार नहीं हुए। कथित तौर पर एआईसीसी ने उनसे कहा था कि सपा को 4-5 और जेडीयू को 1 सीट दें। ऐसे में सवाल बनता है कि अगर उस समय सपा चीफ अखिलेश यादव कमलनाथ के बर्ताव से नाराज हुए थे तो राहुल या खड़गे जैसे नेताओं ने सीधे दखल देने की कोशिश क्यों नहीं की? इसी तरह से कांग्रेस नेताओं ने अपनी राजस्थान यूनिट की भी आलोचना की है। उनको लगता है कि सीपीएम के साथ तालमेल नहीं करने और आदिवासी इलाकों गठबंधन नहीं करने से पार्टी की लुटिया डूब गई है। वहीं अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी पार्टी आलाकमान की आंखों में खटकने लगे हैं। इनके मुताबिक छोटी पार्टियों से दूर रहने का फैसला पार्टी को विधानसभा चुनावों में भारी पड़ गया है। सवाल है कि क्या कांग्रेस आलाकमान को इन चुनावी रणनीतिक खामियों की भनक पहले नहीं लगी थी? अगर उन्हें पहले आगाह किया गया होता तो क्या कमलनाथ, अशोक गहलोत या भूपेश बघेल जैसे क्षेत्रीय नेताओं में राहुल गांधी या खड़गे के निर्देशों की अनदेखी करने की हिम्मत थी? क्या विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं हैं? उन्होंने उनके लिए पनौती मोदी और जेबकतरा जैसे आपत्तिजनक शब्दों तक का इस्तेमाल किया था, जिसमें जेबकतरा पर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। राहुल को अब जिन (फ्लोटिंग) वोटरों को बीजेपी में जाने का दुख सता रहा है, क्या उन वोटरों में से कुछ को उनका आपत्तिजनक बयान प्रभावित नहीं किया होगा? शायद उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को अब इस नकरात्मक प्रचार का एहसास होने लगा है। क्योंकि, सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अब कांग्रेस को नकरात्मक प्रचार से आगे बढ़कर सकारात्मक कार्यक्रम आधारित ऐक्शन पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बात ये है कि कांग्रेस में इस नीतिगत रणनीति में बदलाव की आवाज गांधी परिवार से ही उठी है।

यूपी में भाजपा नये चेहरों पर लगा सकती है दांव

अजय कुमार

आम चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष अप्रैल में राज्यसभा की भी 10 सीटों पर और मई में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा लखनऊ पूर्वी की एक विधान सभा सीट पर भी चुनाव होना है। यहां के भाजपा विधायक गोपाल जी टंडन की हाल ही में मृत्यु हो गई थी। पार्टी के एक उच्च पदस्थ सूत्र का कहना है कि विधान परिषद की कुल 18, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव से पार्टी नए नेतृत्व को मौका देने की शुरुआत करेगी। इनके जरिये पार्टी प्रदेश में अगड़े, पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में अपनी नई लीडरशिप भी तैयार करेगी। पार्टी जिन्हें फिर से विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा जाने का मौका नहीं देगी, उन्हें भी संगठन से जुड़ी कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। जातीय समीकरण साधते हुए इन सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें महिला और युवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। टिकट पाने वालों में पंचायतीराज और नगरीय निकाय संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, सहकारी संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के पूर्व व वर्तमान पदाधिकारी भी शामिल होंगे।

बहरहाल, आम चुनाव तो अगले वर्ष के मध्य से कुछ पूर्व होना है, परंतु इससे पूर्व बीजेपी को कुछ और चुनावों का भी सामना करना है। कुछ दिनों के भीतर सबसे पहले पूर्व लखनऊ पूर्व विधान सभा सीट पर चुनाव होना है। यह सीट बीजेपी विधायक गोपाल जी टंडन की मौत के बाद खाली हुई है। आम चुनाव से पूर्व इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। वह नहीं चाहती है कि यह सीट उसके हाथ से निकल जाये। यदि यहां बीजेपी हार गई तो इसका गलत मैसेज आम चुनाव में भी जायेगा। इसी के साथ कुछ महीनों के भीतर यूपी में राज्यसभा और विधान परिषद की कुछ रिक्त सीटों के लिए भी चुनावी बिसात सजेगी।

बता दें कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कोटे की 10 सीटों का कार्यकाल आम चुनाव से पहले 2 अप्रैल, 2024 को खत्म हो जायेगा। वहीं, विधान परिषद में भी विधायक कोटे की 13 सीटें 5 मई को खाली हो जाएंगी। इसलिए, लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के साथ बीजेपी एवं अन्य दलों को इन सीटों का गुणा-भाग भी दुरुस्त करना पड़ेगा। यूपी कोटे की राज्यसभा की जो 10 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें फिलहाल 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा हैं। सपा से एक मात्र सीट जया बच्चन की खाली होगी। चुनाव आयोग अगले वर्ष मार्च में इसके लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। वहीं, विधान परिषद में खाली हो रही 13 सीटों में 10 भाजपा, एक उसके सहयोगी अपना दल और 1-1 सपा और बसपा के पास है। 5 मई के पहले इन सीटों पर भी चुनाव प्रस्तावित है।

बात राज्य सभा की जो दस सीटें रिक्त हो रही हैं, उसके बारे में की जाये तो इसमें से एक सीट पर मार्च 2018 को हुए राज्यसभा चुनाव में सपा ने जया बच्चन को मैदान में उतारा था और वह चुनाव जीत गई थीं। वहीं एक अन्य सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मायावती से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश में लगी सपा ने बसपा उम्मीदवार भीमराव आंबेडकर को समर्थन दिया था। हालांकि, क्रॉस वोटिंग व संख्या गणित में भाजपा भारी पड़ी और उसने अपने 9 उम्मीदवार जिता लिए थे। सपा से जया बच्चन तो चुनाव जीत गईं, लेकिन बसपा से भीमराव हार गए थे। 2022 के चुनाव के बाद विधानसभा के बदले गणित के चलते इस बार भाजपा के लिए सभी सीटों को बचा पाना मुश्किल होगा, जबकि सपा के पास राज्यसभा में संख्या बढ़ाने का मौका होगा।

बता दें कि विधानसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से राज्यसभा से एक प्रत्याशी जिताने के लिए 37 वोट की जरूरत होगी। सपा के पास 109 और रालोद के पास 9 विधायक हैं। ऐसे में 118 विधायकों के साथ सपा कम से कम तीन सीटें जीतने की स्थिति में होगी। सत्तारुढ़ गठबंधन के पास कुल 279 (भाजपा-254, अपना दल (एस)-13, निषाद पार्टी-6, सुभासपा-6) विधायक हैं। ऐसे में 7 सीटों पर उसकी जीत लगभग तय है। इसके अलावा कांग्रेस के पास 2, जनसत्ता दल के पास 2 व बसपा के पास एक विधायक है। जनसत्ता दल का समर्थन आम तौर पर भाजपा को रहता है। पिछले विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस व बसपा ने किसी भी दल के प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया था। हालांकि, लोकसभा चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ओर नए दोस्तों को जोड़ने-तोड़ने की कोशिशें चल रही है। ऐसे में चुनाव के समय तक दोस्ती व निष्ठा के टिकने-डिगने के आधार पर संख्या व समीकरण आगे-पीछे हो सकता है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इस समय कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है। पिछले साल जुलाई में कांग्रेस पहली बार यूपी के विधान परिषद में शून्य पर पहुंच गई थी। कांग्रेस की स्थिति में फिलहाल आगे भी सुधार होते नहीं दिख रहा है। यही स्थिति इस बार मई में विधान परिषद में बसपा की भी हो सकती है। वह भी शून्य पर पहुंच जाये तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। उसके पास केवल एक विधायक है और इस आधार पर उसका उम्मीदवार पर्चा भी नहीं भर सकता, क्योंकि नामांकन के लिए भी 10 प्रस्तावक की जरूरत होती है। विधानसभा के मौजूदा गणित के हिसाब से विधान परिषद में एक प्रत्याशी जिताने के लिए 29 विधायक की जरूरत पड़ेगी।

जन अदालत में भाजपा की जीत के मंत्र बने मोदी की गारंटी

दीपक कुमार त्यागी

देश के पांच राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पांच में से तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने राजस्थान व छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस पार्टी से छीनकर के सरकार बनाने का कार्य किया है और मध्यप्रदेश राज्य को अपने पास बरकरार रखने कार्य बखूबी किया, वहीं तेलंगाना राज्य में भी भाजपा के वोट प्रतिशत में रिकार्ड वृद्धि हुई है। हालांकि इन तीनों राज्यों में मतदान से कुछ माह पूर्व तक आलम यह था कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन चुनावी रणभूमि में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के चंद राजनेताओं ने जीती हुई बाजी को दिन-रात मेहनत करके पार्टी को हारने का काम बखूबी किया। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने समय रहते ही स्थिति को भांप करके पूरे चुनाव को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम के इर्द-गिर्द करते हुए मोदी की गारंटी के दम पर हारी-बाजी को जीत में बदलने का काम किया है।

चुनाव परिणाम आने के बाद से ही भाजपा में जबरदस्त जश्न का माहौल जारी है, वहीं देश के अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं यह सभी विपक्षी दल अभी भी विधानसभा चुनावों की हार का निष्पक्ष रूप से आंकलन करते हुए अपने-अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार

हैं, वह तो अभी भी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ कर के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के मूड में नज़र आ रहे हैं। मोदी के विपक्ष में खड़े राजनीतिक दलों में से यह कोई भी दल समझने के लिए तैयार नहीं है कि अब उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन वह आत्ममंथन की जगह ईवीएम को ढाल बनाकर उसके पीछे छिपने का कार्य कर रहे हैं।

हालांकि इन विधानसभा के चुनावों में जनता ने विपक्षी दलों के साथ-साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, संघ व एनडीए गठबंधन के अन्य सहयोगियों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि मोदी की गारंटी आज चुनावी जीत का सबसे कारगर मंत्र है, जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति, नियत, नेतृत्व व काम करने की शैली बेहद पसंद है।

वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जोकि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं, जनता को भी मोदी के निर्णय बेहद पसंद आते हैं, क्योंकि नरेन्द्र मोदी ने लोगों के दशकों से इंतजार कर रहे बहुत सारे सपनों को अपने कार्यकाल में धरातल पर अमलीजामा पहना कर साकार करके दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने फैसलों से देश की दुनिया में तस्वीर बदलने व भारत के आम व खास जनमानस की तकदीर को बदलने का काम बखूबी किया है।

उन्होंने अभी तक देश में सड़कों, हाइवे व एक्सप्रेसवे का जाल बिछाना, देश की सीमाओं पर सड़कों का जाल बिछाना, सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना, देश के अलग-अलग हिस्सों में एम्स हॉस्पिटल का निर्माण करना, देश के हर क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय स्तर का मजबूत करना, बंदरगाहों व रेलवे का कायाकल्प करना, देश को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए नये हवाई अड्डे बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को बड़ी संख्या में घर उपलब्ध करवाना, जन-धन खाते खुलवाने, हर घर जल योजना, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत करना, स्वच्छ भारत अभियान चलाना, डिजिटल इंडिया की शुरुआत करना, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी लागू करना, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, तीन तलाक विधेयक लाना, सीएए कानून लाना, जीएसटी लागू करना, कोरोना से बचाव के लिए देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाना, देश की बड़ी आबादी को मुफ्त राशन प्रदान करना, लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने वाली आयुष्मान भारत योजना धरातल पर लागू करना, रेहड़ी पटरी वालो के लिए पीएम स्वनिधि योजना लाना, स्टार्टअप इंडिया योजना के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों को साकार करते हुए विकास को गति देना, अग्निपथ योजना, चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान को भेजना, ज्ञ-20 सम्मेलन की मेज़बानी करना, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, महिला आरक्षण विधेयक आदि वह चंद ऐतिहासिक फैसले है जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के देश के एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों के दिलो-दिमाग पर छा गये हैं। इन फैसलों के दम पर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई है। जिसके चलते ही देश की जनता भी अब राष्ट्रहित में स्थिर, स्थायी और सेवाभाव से समर्पित सरकार के लिए जनादेश देना का कार्य कर रही है। लेकिन विपक्षी दल अब भी उत्तर-दक्षिण भारत का राग अलाप के नकारात्मक राजनीति करने में व्यस्त हैं। वहीं भाजपा में अबकी बार 400 पार सीट लाने की ठोस रणनीति बनाई जा रही हैं। वह मोदी की गारंटी व देश की बहुसंख्यक चार जाति गरीब, महिला, युवा और किसान की बात करके देश से जातिवादी राजनीति का सफाया करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी बड़े पैमाने पर धरातल पर कर रही है।

वैसे भी आज देश में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुत तेजी के साथ अत्याधुनिक मजबूत भारत की नींव रखते हुए बुलंद इमारत बनाने का कार्य बखूबी कर रहे हैं, जिसके चलते ही देश और विदेश के निवेशकों को अब भारत में व्यापार के नये-नये अवसर दिखाई दे रहे हैं, जिससे ही देश की आर्थिक ताकत तेजी बढ रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस आर्थिक ताकत के दम देश की अर्थव्यवस्था को फाइव ट्रिलियन डॉलर की बनाने में जुटे हुए हैं, साथ ही मोदी अर्थव्यवस्था को केवल आंकड़ों तक सीमित ना रखकर के देशवासियों के रोजमर्रा के जीवन में धरातल पर आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, देश के आम जनमानस को उनके हितों के कार्य धरातल पर होते हुए नज़र आ रहे हैं, यही मोदी की गारंटी है और मोदी है तो मुमकिन है नारे का जनता की अदालत में वास्तविक अर्थ है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जनता का यह विश्वास ही भाजपा की जीत का मूल मंत्र है।

सालारः पार्ट 1 - सीज़फ़ायर में प्रभास का एशन पैड रोल देखने लायक, लेकिन कन्यूजिंग स्टोरीलाइन

सालारः पार्ट 1 – सीज़फ़ायर एक निडर आदमी की कहानी है । साल 2017 है । आध्या (श्रुति हासन) लगभग 7 साल तक अमेरिका में छिपने के बाद नकली पासपोर्ट पर भारत आती है । आध्या वाराणसी में रहने के अपने फैसले के बारे में अपने पिता कृष्णकांत को अंधेरे में रखती है । हालाँकि, कृष्णकांत के दुश्मनों को पता चल जाता है और वे अपने लोगों को वाराणसी हवाई अड्डे के बाहर तैनात कर देते हैं । वे आध्या का अपहरण करने का प्रयास करते हैं; दूसरी ओर, कृष्णकांत बिलाल (माइम गोपी) से मदद मांगता है । बिलाल चालाकी से आद्या को उनके चंगुल से छुड़ाता है और उसे असम के तिनसुकिया ले जाता है । यहां वह देवा (प्रभास) को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है । प्रभास की माँ (ईश्वरी राव), जो एक स्कूल की सख्त हेडमास्टर हैं, को आध्या की जान को खतरे के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है । माँ आध्या को अपने स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नियुक्त करती है। अफसोस की बात है कि योजना विफल हो गई क्योंकि कृष्णकांत के दुश्मनों को आध्या के स्थान के बारे में पता चल गया। इस बीच, कांडला बंदरगाह से, एक प्रतिष्ठित मुहर के साथ एक खेप बर्मा की ओर जा रही है। उन लोगों को तिनसुकिया के रास्ते जाने और आध्या का अपहरण करने के लिए कहा जाता है। वे ऐसा करते हैं लेकिन ट्रक को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि देवा आध्या को बचाने की कोशिश करते हुए टीम पर हमला करता है। हालाँकि, ट्रक को सील के साथ रोकना मना है क्योंकि यह एक स्वायत्त, अराजक क्षेत्र खानसार का है। खानसार के वर्धराज (पृथ्वीराज सुकुमारन) को इस उपद्रव के बारे में सूचित किया गया है और कहा गया है कि उसका बचपन का दोस्त देवा ही है जिसने अपराध किया है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। प्रशांत नील की कहानी विस्तृत और काफी कल्पनाशील है । साथ ही सामूहिक क्षणों का अच्छे से ख्याल रखा जाता है । प्रशांत नील की स्क्रिप्ट विशाल और मनोरंजक है। वह दर्शकों को उनके पैसे का मूल्य दिलाने के लिए तनाव औरकमर्शियल क्षणों को बढ़ाने के लिए केजीएफ टेम्पलेट का उपयोग करता है । हालाँकि, खानसार में बहुत सारे किरदार हैं और यह निश्चित रूप से दर्शकों को भ्रमित करेगा । डॉ. सूरी, रिया मुखर्जी और मनीष के हिंदी डायलॉग्स शार्प हैं। प्रशांत नील का निर्देशन अनुकरणीय है । उन्होंने फिल्म को दिलचस्प किरदारों और एक आकर्षक अराजक दुनिया से भर दिया है । चित्रण शानदार है और बड़े स्क्रीन अनुभव के लिए उपयुक्त है। उनकी खासियत यह है कि वे समानांतर सीक्वेंस के जरिए सीन्स में चार चांद लगा देते हैं, जो मुख्य अनुक्रम की तरह ही तनाव से भरे होते हैं। जिस तरह से वह दोनों सीक्वेंस के बीच स्विच करते है और उनके बीच एक सामान्य कारक स्थापित करता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। वह चतुराई से देवा को शुरू में हमला नहीं करने देता, ताकि जब वह ऐसा करे, तो प्रभाव कई गुना अधिक हो। सेकेंड हा? में भी ऐसा होता है, जहां दर्शक उन्माद में डूब जाएंगे । वहीं कमियों की बात करें तो, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यह बेहद जटिल है । खानसार में बहुत सारे खिलाड़ियों के अलावा, उनकी अपनी राजनीति भी है और उनमें से कई एक-दूसरे से संबंधित हैं। दर्शकों को पूरी तस्वीर समझने में कठिनाई होगी और साथ ही संघर्ष भी । दरअसल, पूरे युद्धविराम ट्रैक को समझना आसान नहीं है । क्लाइमेक्स में ट्विस्ट का उद्देश्य दर्शकों को आश्चर्यचकित करना है और ऐसा नहीं होता है। साथ ही, गति धीमी है और पीड़ा के दृश्य चलते रहते हैं। इस फॉर्मूले ने केजीएफ - अध्याय 1 [2018] में अच्छा काम किया लेकिन यहां, प्रभाव सीमित है। एक्टिंग की बात करें तो, प्रभास बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे लेकिन उनका प्रदर्शन आदिपुरुष [2023], राधे श्याम [2022], साहो [2018] आदि में उनके काम से कहीं बेहतर है । वह एक्शन करने में सहज दिखते हैं और उनकी शानदार स्क्रीन उपस्थिति पर्याप्त है ।

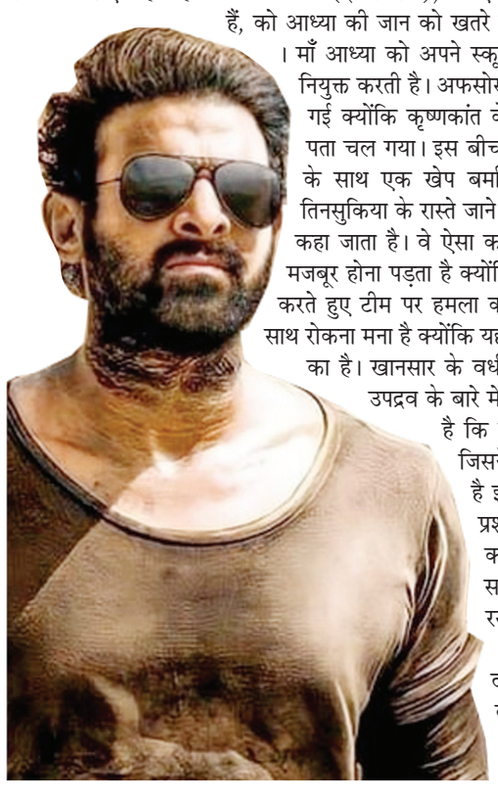

कमजोर लेखन से प्रभावित हुई शाहरुख की डंकी हिरानी की पिछली फिल्मों की तरह उतनी शानदार नहीं है

डंकी बेहतर जीवन के लिए, विदेश जाने की कोशिश कर रहे चार युवाओं की कहानी है । साल है 1995 । आर्मी ऑफिसर हरदयाल सिंह ढिल्लों उर्फ हार्डी (शाहरुख खान) महेंदर से मिलने पंजाब के लाल्टू पहुंचते हैं, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी । वह अपने घर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि महेंद्र अब नहीं रहा । हार्डी को बचाने की कोशिश में महेंद्र ने खेल में एक सुनहरा मौका खो दिया और फिर एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई । हार्डी ने महेंदर के परिवार की मदद करने का बीड़ा उठाया । महेंद्र की बहन मनु (तापसी पन्नू) हार्डी से कुश्ती में उसकी मदद करने के लिए कहती है । ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ब्रिटेन जाकर कमाई करना चाहती है और अपना घर वापस पाना चाहती है जिसे उसके पिता ने कर्ज न चुकाने के कारण खो दिया था । एक एजेंट ने उसे आश्वासन दिया है कि उसे खेल वीजा पर भेजा जा सकता है और लिए, वह खेल की बुनियादी तकनीक सीखना चाहती है । हार्डी उसे कुश्ती सिखाता है । एजेंट मनु, बल्ली कक्कड़ (अनिल ग्रोवर), बुग्गू लखनपाल (विक्रम कोचर) और अन्य ेता है और भाग जाता है । कोई अन्य विकल्प न होने पर, मनु, बल्ली और बुग्गू मदद के (बोमन ईरानी) के पास जाते हैं। वह एक अंग्रेजी भाषी संस्थान चलाता है और ा पास करने की कोशिश करने वालों की मदद करने का वादा करता है । हार्डी के साथ ों में दाखिला लेते हैं। यहां उनकी मुलाकात सुखी (विक्की कौशल) से होती है और पांचों जाते हैं । उनका लक्ष्य किसी भी तरह ब्रिटेन पहुंचना है । आगे क्या होता है इसके लिए होगी । अभिजात जोशी, राजकुमार हिरानी और कनिका ढिल्लन की कहानी शानदार और है, खासकर दक्षिण एशियाई प्रवासी लोगों के लिए । इस क्षेत्र के कई लोगों को इमिग्रेशन क मुद्दा का सामना करना पड़ा है और इसलिए, वे इस कहानी से जुड़ पाएँगे । अभिजात जोशी, राजकुमार हिरानी और कनिका ढिल्लों की स्क्रिप्ट मिक्स है। हालांकि कुछ क्षण इमोशनल और प्रफुल्लित करने वाले हैं, कुल मिलाकर स्क्रिप्ट बहुत बेहतर हो सकती थी, खासकर जब इसे अभिजात और राजकुमार ने लिखा हो । अभिजात जोशी, राजकुमार हिरानी और कनिका ढिल्लों के डॉयलॉग्स कई जगहों पर मजाकिया हैं, लेकिन फिर से, उनके पिछले काम को देखते हुए, वन-लाइनर्स में कहीं अधिक दम होना चाहिए था । राजकुमार हिरानी का निर्देशन सरल है । हमेशा की तरह, वह अपने कॉमेडी-इमोशनल-ड्रामा फॉर्मूले का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं । इसलिए, फिल्म कभी भी धीमी या उबाऊ नहीं होती । कोई भी बोरिंग पल नहीं है । फिल्म वर्तमान समय में शुरू होती है और जिस तरह से गतिशीलता दिखाई गई है, किसी को यह जानने की उत्सुकता हो जाती है कि किरदारों के साथ क्या हुआ होगा । यह 3 इडियट्स [2009] की शुरुआत का एक दृश्य भी देता है । वे दृश्य जहां हार्डी और उनकी टीम अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं और उनके वीज़ा साक्षात्कार देखने लायक हैं । इंटरमिशन प्वाइंट काफी मजबूत है । सेकेंड हाफ़ में, यूके कोर्ट में हार्डी के दृश्य और पूरे सऊदी अरब का दृश्य फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा बन जाता है । फ़िल्म का एंड प्रेरक है, और उल्लिखित आँकड़े काफी कठिन और निराशाजनक हैं । शुक्र है, अंतिम दृश्य मज़ेदार है, और फ़िल्म हल्के-फुल्के अंदाज में ख़त्म होती है। वहीं फ़िल्म की कमियों की बात करें तो, राइटिंग उतनी भी अच्छी नहीं है । निर्माताओं ने परिवारों और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है । दर्शकों को यह महसूस होना चाहिए कि किरदारों के पास यूके जाने का एक मजबूत कारण था ।

महाठग सुकेश ने अपने लैटर में जैकलीन को दी एसपोज करने की धमकी

'दुनिया को सच्चाई जानने की जरूरत है'

200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिलेशन रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं । जैकलिन फर्नांडीज के खिलाफ दाखिल मनी लांड्रिंग के मामले रद्द करने की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा है । इसके अलावा जैकलीन ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सुकेश को उनके खिलाफ जानकारी को देने से रोकने का निर्देश दिया जाए । वहीं महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने कथित तौर पर जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ कुछ अनदेखे सबूतों को उजागर करने की धमकी दी है । खबरों के मुताबिक, सुकेश ने जैकलीन का नाम लिए बगैर एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने कहा है कि वह एक व्यक्ति को एक्सपोज करने वाला है । इसके लिए वह उस व्यक्ति के चैट्स, स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स को रिलीज करेगा । रिपोर्ट के अनुसार, सुकेश ने दावा किया कि उसने इस व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट की रीच बढ़ाने के लिए पेमेंट की थी, ताकि इस व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अपने प्रमुख सहयोगी के खिलाफ बढ़त मिल सके । 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश ने चिट्ठी में लिखा है, दुनिया को सच्चाई जानने की जरूरत है. असल सच्चाई. वहीं, सुकेश की चिट्ठियों को लेकर जैकलीन ने बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया । उन्होंने मंडोली जेल के अधीक्षक और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को निर्देश देने की मांग की कि वे चंद्रशेखर को उनके बारे में कोई और चिट्ठी, बयान या मैसेज जारी करने की अनुमति न दें । दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर अगले साल 29 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा । गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने भी जैकलीन की याचिका पर अपना विरोध जताया है । प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि जैकलीन, सुकेश चंद्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानते हुए भी उससे महंगे-महंगे गिफ्ट्स लेती रहीं । वहीं जैकलीन का कहना है कि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का तो कोई केस बनता ही नहीं है। इस पूरे मामले में जैकलीन का कहना है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता । दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज केस में मैं आरोपी नहीं हू । उसमें मैं अहम गवाह हूं । ईओडब्ल्यू का कहना है कि मैंने जब सुकेश से गिफ्ट लिए तब मुझे सुकेश की आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ईडी ने इस पूरे मामले में मुझे मुख्य आरोपी बना दिया ।

अब लोग फिल्म को एटर की एटिंग से नहीं बल्कि फिल्म के कलेशन से पहचान रहे हैं ; सब के सब मुंशी बन रहे हैं

महामारी के बाद से लोगों का सिनेमा के प्रति नज़रिया काफ़ी बदल गया है और ये रिलीज हो रही फ़िल्मों को मिली प्रतिक्रिया से पता लगाया जा सकता है । थिएटर में कमोबेश लार्जर देन लाइफ़ फ़िल्में ही अपने लिए दर्शक जुटा पा रही हैं जबकि कंटेंट बेस्ड फ़िल्मों को थिएटर में संघर्ष करना पड़ रहा है । नतीजतन अब लोग फ़िल्म को, उसके शानदार निर्देशन, एक्टिंग से नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पहचान रहे हैं । इसी पर नाराज़गी जताते हुए बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड हंगामा के एक्सक्लूसिव एक्टर्स राउंड टेबल में कहा कि अब सब के सब मुंशी बने फिर रहे हैं । नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा कि, हालत ये है कि अब दर्शक भी कलेक्शन की भाषा बोलने लगे हैं । बॉलीवुड में बढ़ते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के क्रेज़ पर नाराज़गी जताते हुए नवाज़ ने कहा, पहले जब मैं कॉलेज में था, तो फ़िल्म देखकर आते थे तो कहते थे कि आज फ़लां फ़िल्म में उस एक्टर ने क्या काम किया है, बेहतरीन । तो उस वक्त हम एक्टर की एक्टिंग देखने के लिए फ़िल्म देखते थे । हमने बेहतरीन एक्टिंग को देखने के लिए बहुत सारी फ़िल्में देखी है जैसे- परिंदा, सत्या, बैंडिट क्वीन और भी कई सारी । क्योंकि उस समय एक्टर की एक्टिंग के बारें में बातें होती थी । लेकिन अब ऐसा नहीं है । आज की डेट में क्या हो रहा है, कितना कलेक्शन हुआ- अच्छा 100 करोड़, 200 करोड़, लोग फ़िल्म के कलेक्शन के हिसाब से बात करते हैं और कलेक्शन से ही फ़िल्म को पहचानते हैं । अरे तुम क्या मुंशी बनने आए हो क्या? फ़िल्म की कमाई का तो ऐसे हिसाब-किताब लगाते है मानो सभी सीएन बन रहे हो। हालत ये है कि अब दर्शक भी कलेक्शन की भाषा बोलने लगे हैं ।

प्रभास को लेकर सालार के एक्टर का खुलासा! बोले- उनके साथ काम करना है मुश्किल, एक अलग कमरा...

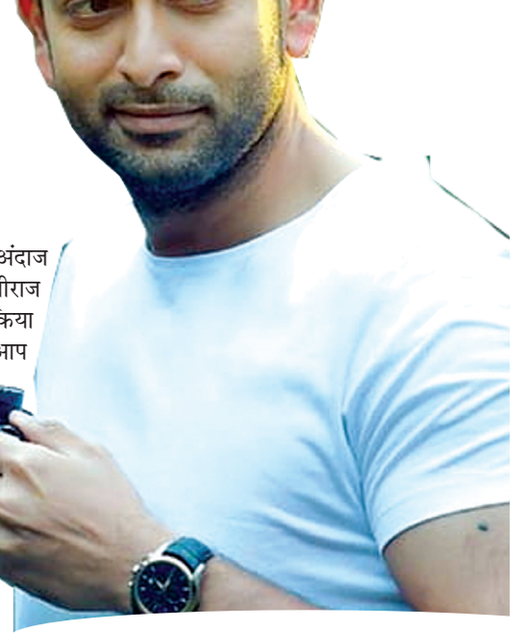

पर्दे पर बेहद एग्रेसिव और एंग्री यंग मैन नजर आने वाले बाहुबली स्टार प्रभास असल में कैसे होंगे. क्या वो सेट पर भी गुस्सैल या दबंग अंदाज में रहते होंगे या, फिर उनका मिजाज बहुत दोस्ताना होगा. इस बारे में उनके को स्टार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. ये कोस्टार हैं पृथ्वीराज सुकुमारन. जिन्होंने खुलासा किया है कि प्रभास के साथ काम करना मुश्किल है. प्रभास ने एक बार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कुछ ऐसा ही किया जिसके बाद उन्हें अलग से कमरा तक लेना पड़ गया. ये बात अलग है कि प्रभास ने जो किया उसे सुनकर आपको गुस्सा नहीं आएगा बल्कि आप एक बार फिर प्रभास के मुरीद हो जाएंगे. हाल ही में पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया कि प्रभास के साथ काम करने में सबसे बड़ी खराबी क्या है. तेलुगु फेब नाम के ट्विटर हैंडल पर उनके हवाले से इस बारे में जानकारी शेयर की गई है. जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया कि प्रभास ने उनकी बेटी से पूछा कि उसे खाने में क्या पसंद है. बेटी का जवाब सुनकर प्रभास अगले दिन इतनी सारी चीजें लाए कि उन्हें रखने के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन को एक अलग कमरा लेना पड़ गया. इस जानकारी को शेयर करते हुए तेलुगु फेब ने कैप्शन लिखा है कि वो अपने प्यार से सब की जान ले लेता है. जिस पर एक यूजर ने कमेंट किया कि वो इसी वजह से सबके डार्लिंग स्टार हैं. आपको बता दें कि प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन बहुत जल्द एक साथ स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं. दोनों सालार में एक साथ दिखें. इस फिल्म में तेलुगु स्टार प्रभास और मलयालम फिल्म के दिग्गज पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार साथ काम करने वाले हैं. सालार एक जबरदस्त एक्शन मूवी है. जिसमें फिर से प्रभास का बाहुबली वाला जलवा नजर आएगा.

दूसरी शादी करने जा रहे हैं अरबाज, शूरा खान बनेगी दुल्हन

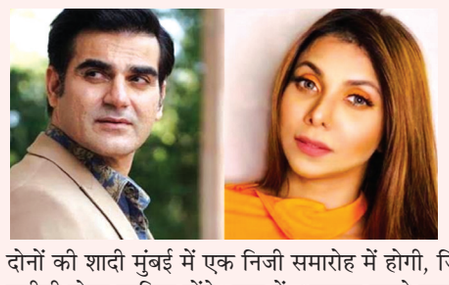

बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान सुर्खियों में हैं। अभिनेता की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर छायी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अरबाज 24 दिसंबर को मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी करने जा रहे हैं। दोनों की शादी मुंबई में एक निजी समारोह में होगी, जिसमें परिवार वालों के अलावा करीबी दोस्त शामिल होंगे। बता दें, अरबाज इससे पहले अभिनेत्री जियोर्जिया के साथ रिश्ते में थे। दोनों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। अरबाज और जॉर्जिया एंड्रियानी के ब्रेकअप की पुष्टि खुद अभिनेत्री ने की थी। जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ ब्रेकअप के बाद अब अरबाज खान दूल्हा बनने के लिए तैयार है। अभिनेता मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से निजी समारोह में निकाह रचाने वाले हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में अरबाज की शादी की पुष्टि की गयी है। रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म पटना शुक्ला के सेट पर अरबाज और शुरी की मुलाकात हुई थी। बता दें, शूरा एक बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी के साथ काम किया है। जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट करने से पहले अरबाज खान बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरो?ा के साथ थे। दोनों ने 1998 में शादी की थी। शादी के 19 साल बाद मार्च 2016 में मलाइका और अरबाज ने एक-दूसरे से अलग होने का फैसला किया। 11 मई, 2017 को आधिकारिक तौर पर दोनों का तलाक हो गया।

मैं हमेशा से चाहती थी कि एक अभिनेत्री के रूप में लोग मुझे गंभीरता से लें

अनन्या ने कहा, मैं सोच-समझकर कोई फैसला नहीं कर रही हूं। मेरी अपनी पसंदहै और मैं गुप्त रूप से यह बता रही हूं कि मैं किसके साथ काम करना चाहती हूं लेकिन अच्छे काम से बेहतर कोई दूसरी चीज नहीं है अभिनेत्री अनन्या पांडे का कहना है कि अच्छे काम से बेहतर कोई दूसरी चीज नहीं है और वह चाहती हैं कि फिल्मों का उनका चयन एक अभिनेत्री के तौर पर उनके बेहतर होते अभिनय को दर्शाए। निर्माता करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अनन्या को शकुन बत्रा द्वारा निर्देशित फिल्म गहराइयां में उनके अभिनय के लिए काफी प्रशंसा मिली थी। अनन्या (25) ने पीटीआई- से कहा, मैं हमेशा से चाहती थी कि एक अभिनेत्री के रूप में लोग मुझे गंभीरता से लें। ऐसा नहीं है कि गहराइयां के बाद यह (पसंद) बदल गई है। मेरी उम्र 20 साल से ज्यादा है और बढ़ती उम्र के साथ मैं बहुत सी चीजों से जुड़ रही हूं। उन्होंने कहा, मैं विभिन्न प्रकार की फिल्में करना चाहती हूं। यह एक व्यक्ति के रूप में मेरे विकास से जुड़ा है। मेरी पसंद भी बदल रही है। अनन्या ने कहा, मैं सोच-समझकर कोई फैसला नहीं कर रही हूं। मेरी अपनी पसंदहै और मैं गुप्त रूप से यह बता रही हूं कि मैं किसके साथ काम करना चाहती हूं लेकिन अच्छे काम से बेहतर कोई दूसरी चीज नहीं है। मैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हूं। अभिनेत्री ने कहा कि वह आभारी हैं कि बत्रा, अख्तर और मोटवानी जैसे फिल्म निर्माताओं ने उनपर विश्वास जताया।

अपने ही देश में सुरक्षित महसूस नहीं करतीं पाक एट्रेस आयशा

आयशा उमर पाकिस्तान में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह एक यूट्यूबर भी हैं और देश की स्टाइल आइकन के रूप में जानी जाती हैं। अब आयशा ने एक बेहद चौंकाने वाली बात शेयर की है। आयशा उमर पाकिस्तान में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह एक यूट्यूबर भी हैं और देश की स्टाइल आइकन के रूप में जानी जाती हैं। अब आयशा ने एक बेहद चौंकाने वाली बात शेयर की है। उन्होंने पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि देश में महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे वह देश में सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। महिला को कम उम्र में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और 2015 में एक घातक दुर्घटना का भी सामना करना पड़ा था। अब, अदनान फैसल पॉडकास्ट से बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वह देश में सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। वह स्वतंत्र रूप से चलना चाहती है और बाहर खुली हवा में चलने में सक्षम होना एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सड़कों पर चलने में सुरक्षित महसूस नहीं करतीं और वह हमेशा कार में नहीं बैठना चाहतीं। वह साइकिल या बाइक चलाना चाहती है। उन्होंने कहा, पुरुष कभी नहीं समझ सकते कि पाकिस्तानी महिलाएं किसके साथ बड़ी होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में एक महिला को जिस डर का सामना करना पड़ता है, उसे केवल वही लोग समझ पाएंगे जिनकी बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमेशा चिंतित रहती हैं और महिलाओं को समझना असंभव है। उन्होंने उस समय को याद किया जब उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और कहा कि उनके पड़ोसी के रसोइये ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। इसके बाद उन्होंने कहा कि पॉश इलाकों में भी वह असुरक्षित महसूस करती हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अस्पतालों में नकली दवाएं एलजी ने दिए जांच के आदेश

नईदिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जा रही गैर-मानक दवाओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश की है। मुख्य सचिव को लिखे एक नोट में सक्सेना ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण की गई ये दवाएं मानक गुणवत्ता की नहीं निकलीं। उन्होंने कहा कि ये दवाएं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लाखों मरीजों को दी जा रही हैं और संभवत: इन्हें मोहल्ला क्लीनिकों में आपूर्ति की जा रही हैं। सक्सेना ने दवाओं की खरीद में भारी बजटीय आवंटन पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि इस अभ्यास में अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्ता और निर्माता शामिल थे। घटिया दवाओं के मामले पर सतर्कता निदेशालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, सरकारी प्रयोगशालाओं को भेजे गए 43 नमूनों में से तीन गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे, जबकि 12 रिपोर्ट अभी भी लंबित हैं।

कार्ति चिदंबरम धनशोधन के मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम 2011 में कुछ चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से जुड़े धनशोधन के मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक, ईडी का मामला वेदांत समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के एक शीर्ष कार्यकारी द्वारा कार्ति और उनके करीबी सहयोगी एस भास्कररमण को रिश्वत के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने के आरोपों से संबंधित है। टीएसपीएल पंजाब में एक बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही थी। ईडी का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है। एजेंसी तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद कार्ति चिदंबरम (52) का धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बयान दर्ज करेगी।

तेजस्वी को ईडी ने पांच जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया

पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'नौकरी के बदले जमीन' यानी लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नया समन जारी किया है। उन्हें पांच जनवरी को पेश होने को कहा गया है। खबरों की मानें तो तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय बुलाया है। अगले सप्ताह ईडी तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को इडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। इडी ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में शुक्रवार को उन्हें नयी दिल्ली स्थित प्रवर्तन कार्यालय के दफ्तर में आकर बयान दर्ज कराने को समन भेजा था। लेकिन, तेजस्वी शुक्रवार को राजधानी पटना में ही नजर आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले कहा था कि वे ईडी समेत जांच एजेंसियों को सहयोग करते रहे हैं। इडी के समन को लेकर कहा था कि यह चुनाव का समय है। ऐसा चलता रहेगा।

जदयू अध्यक्ष पद फिर से खुद संभाल सकते हैं नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख के पद से हटा सकते हैं। यह फैसला 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लिए जाने की संभावना है। कयासों के बीच सूत्रों ने कहा कि नीतीश कुमार खुद पार्टी प्रमुख का पद संभाल सकते हैं। यह भी समझा जाता है कि नीतीश को उनके करीबी विश्वासपात्रों ने सलाह दी है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए क्योंकि इससे पार्टी के भीतर किसी भी तरह की कलह से बचने में मदद मिलेगी, जो अन्यथा ललन सिंह की जगह किसी नए चेहरे के कारण शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, नीतीश, ललन सिंह के कामकाज के तरीके और खासकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों को लेकर नाराज हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि ललन सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से मुंगेर से लड़ने के इच्छुक हैं और वह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।

हिम्मत है तो वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को 2024 के आम चुनाव के लिए वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक के दौरान बनर्जी द्वारा वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने के बाद पॉल की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे से पहले अगर ममता बनर्जी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की जगह चुनाव लड़ने की हिम्मत है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं न? हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुकाबला करेंगे। देखते हैं उसमें कितना साहस है। 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया, लेकिन यह तब शांत हो गया जब कांग्रेस ने अजय राय को मैदान में उतारा।

टेरर एक्टिविटी पर विदेश मंत्री ने दहशतर्दों के हिमायतियों को चेताया

सीमा पार आतंकवाद की चुकानी होगी कीमतः जयशंकर

नईदिल्ली। आतंकवाद पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद हमारी आजादी के समय ही शुरू हो गया था, जब तथाकथित हमलावर पाकिस्तान से आए थे। आज इस देश में क्या बदलाव आया है, मुझे लगता है कि मुंबई 26/11 एक निर्णायक बिंदु था। बहुत से लोग तब तक बहुत भ्रमित थे जब तक उन्होंने 26/11 के आतंकवाद के वास्तविक प्रभावशाली प्रभावशाली चरण को नहीं देखा था। अब, हमें सबसे पहले जो करने की ज़रूरत है वह यह है कि हमें मुकाबला करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ देश का मूड है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रणनीतिक मतलब है। अगर कोई अभ्यास कर रहा है सीमा पार आतंकवाद का आपको जवाब देना होगा, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी।

सीमा पार हमलों के बीच पाकिस्तान सेना प्रमुख की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के मुद्दों पर भारत ने प्रतिक्रिया

दी। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर की पहली अमेरिकी यात्रा पर बोलते हुए भारत ने आतंकवाद और सीमा पार हमलों के लिए इस्लामाबाद के समर्थन पर अपनी चिंता दोहराई। नई दिल्ली को उम्मीद है कि अन्य देश आतंकवाद के खिलाफ उचित गंभीरता से व्यवहार करेंगे। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 सितंबर को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एफ-16 रखरखाव पैकेज के बारे में चिंता जताई।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को संसद से तीन आपराधिक विधेयकों के पारित होने की सराहना की और इसे औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलने और भारत के उद्भव के लिए उपनिवेशवाद से मुक्ति में मील का पत्थर कहा। उन्होंने आगे कहा कि कानूनी, पुलिस और जांच प्रणालियों को अद्यतन करने से कमजोर लोगों के लिए सुरक्षा बढ़ती है और संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी प्रतिक्रिया की सुविधा भी मिलती है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वे हमारे उपनिवेशवाद से मुक्ति और भारत के उद्भव में मील के पत्थर हैं।

राजद और जदयू का शीघ्र होगा विलय!

नीतीश और लालू राजनीति में करेंगे भूचालः गिरिराज

पटना। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने शनिवार को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विलय की ओर बढ़ रहे हैं। बयान पर बिहार की सियासत में कयासबाजी का दौर भी तेज हो गया है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा का बाजार फिर से गर्म है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव कोई ऐसा फैसला करेंगे जो सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेर की बानगी बनेगा। इसमें जदयू का राजद में विलय होने की बातें सबसे प्रमुख है। अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार ही नहीं देश की सियासत के लिए एक बड़े बदलाव का सूचक बन जाएगा।

वहीं कई स्थापित राजनेताओं का कद भी बदल जाएगा। उल्लेखनीय है कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि जदयू टूटने की ओर बढ़ रही है और अगले चुनाव से पहले जदयू का राजद में विलय हो जाएगा। अब सुशील मोदी की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी यही दोहराया है।

उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू राजद में विलय होने वाली है और नीतीश कुमार की भूमिका भी तय कर दी गई है। ऐसे में भाजपा नेताओं के इन दावों ने सियासी भूचाल मचा दिया है। इस बीच, 29 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। इस को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चर्चा यह कि इस बैठक में नीतीश कुमार ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने के अलावे जदयू का राजद में विलय संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगवा सकते हैं। इसको लेकर जोरदार चर्चा है। हालांकि शनिवार को ललन सिंह ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। इस बीच दावा यह भी किया जा

रहा है कि ललन सिंह की इन दिनों लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी हो गए हैं। ऐसे में राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर दोनों दल एक साथ आते हैं तो इससे उनके साथ रहने वाले कई नेताओं को झटका लगेगा।

सिंह ने शरारती अंदाज में कहा, '' लालू जी से मेरा व्यक्तिगत समीकरण है। उन्होंने मेरे कान में कई ऐसी बातें कहीं जिन्हें मैं सार्वजनिक रूप से सामने नहीं रख सकता। लेकिन मैं आपको इतना तक बता दूं कि जदयू का शीघ्र ही राजद के साथ विलय होने जा रहा है।'' उल्लेखनीय है कि प्रसाद और सिंह हाल में दिल्ली से लौटते समय एक ही विमान में थे। राजद सुप्रीमो प्रसाद विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन में भाग लेने दिल्ली गये थे जबकि केंद्रीय मंत्री अभी-अभी समाप्त हुए संसद के सत्र में हिस्सा ले रहे थे। बृहस्पतिवार शाम को पटना पहुंचने पर सिंह ने पत्रकारों से कहा था कि विमान में उनके चिर प्रतिद्वंद्वी प्रसाद ने उनसे कहा था, '' (बेटे और उपमुख्यमंत्री) तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का वक्त आ गया है।'' तेजस्वी यादव जोकि उसी विमान में मौजूद थे, ने उनके और नीतीश कुमार के बीच दूरी पैदा करने की (सिंह की) कोशिश को बाद में यह दावा करते हुए खारिज कर दिया कि असल में केंद्रीय मंत्री (सिंह) ने उनसे और उनके पिता के साथ बातचीत के दौरान भाजपा और केंद्र सरकार में अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

भारत के दरवाजे तक पहुंची हूतियों की हिंसा! गुजरात के पास टैंकर जहाज पर हमला

नईदिल्ली। भारतीय तट के पास हिंद महासागर में लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया है। अरब सागर में हुए इस हमले की कई रिपोर्टों में पुष्टि हुई है। एएफपी ने दो समुद्री एजेंसियों के हवाले से बताया कि शनिवार को एक ड्रोन हमले में भारत के तट पर एक व्यापारी जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इनमें से एक जहाज इजराइल से संबद्ध व्यापारिक जहाज है, जिस पर भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में मानवरहित ड्रोन ने हमला कर दिया, जिससे जहाज में आग लग गई।

भारतीय रक्षा अधिकारियों ने कहा कि भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस विक्रम पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें ड्रोन हमले के कारण आग लगने की घटना की आशंका है। रक्षा अधिकारियों ने यह भी कहा कि जहाज में कच्चा तेल है और यह सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मैंगलोर की ओर जा रहा था। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि अरब सागर में एमवी केम प्लूटो के आसपास भारतीय नौसेना के युद्धपोत भी बाहरी भारतीय ईईजेड में व्यापारी जहाज की ओर बढ़ रहे हैं।

भारतीय तट रक्षक जहाज आईसीजीएस विक्रम पोरबंदर लागत से 217 समुद्री मील दूर अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो की ओर बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि इसमें ड्रोन हमले के कारण आग लगने की घटना की आशंका है। जहाज में कच्चा तेल है और यह सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मैंगलोर की ओर जा रहा था।

राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों की संख्या कम होने के कारण आतंकी हुए एक्टिव?

नईदिल्ली। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि पुंछ और रजौरी सूरनकोट जैसी जगहों में काफी ज्यादा आतंकी घटनाएं बढ़ गयी है। पीर पंजाल इलाका काफी ज्यादा असुरक्षित हो गया है। पहले इन इलाकों में आतंकियों को कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन अब एक बार यहां पर खतरा और ज्यादा पढ़ गया है। पहले नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल से आतंकी ज्यादा घुसपैठ करते थे क्यों कि वहां पर काफी बड़े पहाड़ थे तो सुरक्षा ग्रीडों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती थी उसकी तुलना में साउथ ऑफ पीर पंजाल में पहाड़ कम थे इस लिए इस तरफ से खतरा ज्यादा होता था। घुसपैठ करने के लिए बहुत बड़ी पहाड़ी को पार नहीं करना होता था। वहां पर सुरक्षा ग्रिड मजबूत होने के बात आतंकी घुसपैठ को कंट्रोल कर लिया गया। आतंकवाद की घटनाएं कम होने के बाद यहां से राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों की संख्या कम कर दी गयी थी क्योंकि चीन की तरफ ज्यादा खतरा बढ़ रहा था। राष्ट्रीय राइफल्स एक अलग तरह से काम करती हैं वह घुसपैठियों को धर दबौचती हैं। लेकिन ऐसा लगता है अब एक बार फिर से पीर पंजाल में आतंकी डेरा डाल चुके हैं। यह तक इस इलाके में 10 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में यहीं के जंगल वाले इलाके में दो अलग-अलग आतंकी हमलों में 9 सैनिक शहीद हो गए।

खेल
प्रमुख समाचार

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए ऋतुराज

मुंबई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। पहला टेस्ट सेंचुरियन में खेला जाएगा। वहीं, दूसरा टेस्ट तीन जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका में कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में इस बार भारतीय टीम इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ऋतुराज गायकवाड़ अंगुली में फ्रैक्चर के साथ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। ऋतुराज इसके अलावा एक टेस्ट के लिए इंडिया-ए टीम में भी थे। बीसीसीआई ने शनिवार को इसका आधिकारिक एलान किया है और रिप्लेसमेंट की घोषणा भी कर दी है। ऋतुराज के रिप्लेसमेंट के तौर पर जिस खिलाड़ी को टीम में लाया गया है, वह इंडिया-ए टीम की कप्तान कर चुका है और घरेलू क्रिकेट में उनके नाम काफी रन हैं। वहीं, दक्षिण अफ्रीका में ही मौजूद सरफराज खान की एक बार फिर अनदेखी की गई है।

बीसीसीआई ने ऋतुराज का हेल्थ अपडेट देते हुए कहा- उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में फील्डिंग करते हुए दाएं हाथ की अंगुली में चोट लग गई थी। उनका स्कैन किया गया और विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें दौरे के बाकी मैचों से बाहर कर दिया। वह अपनी चोट के आगे के प्रबंधन के लिए एनसीए को रिपोर्ट करेंगे। पुरुष चयन समिति ने उनकी जगह अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किया है। ऋतुराज वनडे और टी20, दोनों में डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन टेस्ट में उन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। वहीं, ईश्वरन बंगाल की टीम से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उनके पास 88 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का अनुभव है और वह पहले भी टीम इंडिया में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका नहीं मिला है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट से 60 करोड़ डॉलर जुटाए

नईदिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अमेरिका की दिग्गज खुदरा कंपनी वॉलमार्ट से लगभग पांच-10 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन पर 60 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। कंपनी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उसने वॉलमार्ट से 60 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। सूत्रों ने कहा कि यह राशि वास्तविक आंकड़ों का खुलासा किए बिना पांच-10 प्रतिशत की सीमा में उच्च मूल्यांकन पर आई है। फ्लिपकार्ट ने अपनी मूल कंपनी से हालिया धन जुटाने के बाद कंपनी के मूल्यांकन पर कोई टिप्पणी नहीं की। फ्लिपकार्ट का पिछली बार मूल्यांकन 37.6 अरब डॉलर या 2.79 लाख करोड़ रुपये किया गया था, जब इसने जीआईसी, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, सॉफ्टबैंक विजन फंड 2, वॉलमार्ट, डिसरप्टएडी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टाइगर ग्लोबल आदि से 3.6 अरब डॉलर (लगभग 26,800 करोड़ रुपये) जुटाए थे।

बिजलीघरों का विद्युत उत्पादन अप्रैल-नवंबर में 8.39% बढ़ा

नईदिल्ली। घरेलू कोयला आधारित बिजलीघरों से विद्युत उत्पादन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान 8.38 प्रतिशत बढ़कर 779.1 अरब यूनिट रहा। एक अधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि एक साल पहले इसी अवधि में घरेलू कोयला आधारित बिजलीघरों से विद्युत उत्पादन 718.83 अरब यूनिट रहा था। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में बिजली उत्पादन आलोच्य अवधि में 7.71 प्रतिशत बढ़ा है। कुल मिलाकर कोयला आधारित बिजलीघरों (आयातित कोयला मिलाकर) के उत्पादन में चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान सालाना आधार पर 11.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका कारण गर्मी का बढ़ना, देश के उत्तरी भाग में मानसून में देरी के साथ कोविड महामारी के बाद वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी है।

असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर रिटर्न फॉर्म एक और चार अधिसूचित

नईदिल्ली। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार को अधिसूचित कर दिया है। इस फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं। इससे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के अलावा, 50 लाख रुपये तक की आय वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2023-मार्च 2024) में कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर, वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किये जाते हैं। हालांकि, इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिये गये हैं।

ओडिशा ने 1,482 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी

भुनेश्वर। ओडिशा सरकार ने 1,482.53 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सात औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 11,500 से अधिक नौकरियां सृजित होंगे। प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा, मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना के नेतृत्व में राज्य स्तरीय एकल मंजूरी प्राधिकरण (एसएलएसडब्ल्यूसीए) ने शुक्रवार को खुर्दा, गंजाम, सुंदरगढ़, क्योंझर, जाजपुर, बालेश्वर और रायगड़ जिलों में स्थापित होने वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। बयान के अनुसार, एसएलएसडब्ल्यूसीए ने क्योंझर जिले में 800 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्टील विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए टेक एआईसी डीआरआई पेलेट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

भूटान का ऐतिहासिक आर्थिक निर्णय

डॉ धनंजय त्रिपाठी

इतिहास को देखें, तो भूटान बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क रखने की नीति पर चलता रहा है। उसने अपने यहां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर होने में भी दिलचस्पी नहीं दिखायी है, लेकिन अब इस स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन होने जा रहा है। भूटान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने एक हजार वर्ग किलोमीटर में एक विशाल हरित शहर बनाने की घोषणा की है, जिसके नियम-कानून भी अलग होंगे। भारत के असम से सटे इलाके में प्रस्तावित इस स्मार्ट सिटी के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और कंपनियों को आमंत्रित किया जायेगा। भूटान के राजा ने उचित ही रेखांकित किया है कि यह विशाल परियोजना भूटान और दक्षिण एशिया में बड़े बदलाव का माध्यम बनेगी तथा इसके जरिये दक्षिण एशिया का जुड़ाव दक्षिण-पूर्व एशिया से हो जायेगा। क्षेत्रीयता की दृष्टि से देखें, तो यह विस्तृत शहर भूटान, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ-साथ भारत के पूर्वोत्तर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। सीमित संपर्क और अर्थव्यवस्था के देश भूटान के लिए यह बड़ी नीतिगत छलांग है तथा अब वह उदारीकरण एवं व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के दौर में प्रवेश कर रहा है।

इस परियोजना का आधार तब तैयार हुआ था, जब हाल में भूटान के नरेश भारत के दौरे पर आये थे। उस समय भारत और भूटान के बीच एक रेल नेटवर्क बनाने का समझौता हुआ था। अपने संबोधन में भी भूटान नरेश ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद दिया

है। यह रेल नेटवर्क भूटान के गेलेफु को भारत के असम और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। इससे सड़क मार्ग और सीमा कारोबारी चौकी भी जुड़े होंगे। भूटान इससे म्यांमार, थाइलैंड, कंबोडिया और सिंगापुर से जुड़ जायेगा। भूटान इस परियोजना को लेकर सही ही उत्साहित है। वहां के नरेश ने कहा है कि मार्गों से बाजारों, पूंजी, नये विचारों एवं तकनीक, भविष्य और भाग्य के नये अवसरों के द्वार खुलेंगे। विश्व बैंक ने कहा है कि भूटान अब सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी से ऊपर उठ चुका है, लेकिन अभी भी वहां बेरोजगारी दर बीस फीसदी के आसपास है और हाल के समय में सकल घरेलू उत्पाद में कमी आयी है। पर्यटन भी कम हुआ है। ऐसे में यह परियोजना भूटान का कायाकल्प करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया को अपने पड़ोसी क्षेत्रों- मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया- से संपर्क और सहकार बढ़ाना चाहिए। मध्य एशिया में तेल और गैस का भंडार है, जो दक्षिण एशिया की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार हो सकता है। दक्षिण-पूर्व एशिया ने हाल के दशकों में शानदार विकास किया है तथा वहां संसाधन भी हैं। उस बाजार से जुड़ना दक्षिण एशिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक ओर भूटान भारत के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार से अपनी आर्थिक नीति में बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है, वहीं वह एक और बड़े पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान कर कूटनीतिक और आर्थिक सहकार के लिए प्रयासरत है। यह भी एक बड़ा बदलाव है। ऐतिहासिक रूप से भूटान का बाहरी संबंध मुख्य रूप से भारत से ही था। अभी डेढ़ दशक पहले तक दोनों देशों के बीच समझौता था कि भूटान की विदेश नीति के बारे में निर्णय भारत करेगा। अब संकेत स्पष्ट हैं कि भूटान विकास के लिए प्रयासरत है और इसके लिए भारत और चीन दोनों का सहयोग लेना चाहता है। इससे भूटान अपने दो विशाल पड़ोसियों के बीच संतुलन भी स्थापित कर सकता है। यह न केवल भूटान के हित में है, बल्कि उस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी वांछनीय है। यह अलग चर्चा का विषय है कि इस हरित शहर परियोजना में चीन की भूमिका क्या होगी और दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व के बीच की संभावित कनेक्टिविटी को लेकर उसका रवैया क्या होगा।

कही-सुनी

रवि भोई

छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा दिल्ली से

चर्चा है कि भाजपा हाईकमान और संघ के इशारे पर ही छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का नाम तय हुआ। अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी दिल्ली से हरी झंडी मिलने पर होगा। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंत्रियों के विभागों में मुहर लगाएंगे। मंत्रियों के विभाग बंटवारे में एक-दो दिन समय लगने की संभावना है। मंत्रियों के विभाग बंटने के बाद शीर्ष स्तर के आईएएस-आईपीएस और आईएफएस अफसरों के विभागों में हेरफेर किया जाएगा। कलेक्टर-एसपी के भी तबादले होंगे। कहते हैं कि मंत्रियों के विभागों को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और मनसुख मंडविया से चर्चा की। प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय, क्षेत्रीय महासचिव (संगठन) अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि सभी से चर्चा के बाद मंत्रियों के विभाग तय किए जाएंगे। हालांकि इस बीच मंत्रियों के विभागों की फर्जी सूची खूब वायरल हो रही है। भाजपा को नतीजे आने के बाद करीब एक हफ्ते मुख्यमंत्री चयन में लगा।13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ के बाद 22 दिसंबर को मंत्रियों की शपथ हुई। विभागों के बंटवारे में तो कुछ दिन लगेंगे ही।

नाम ही नहीं, काम के भी उपमुख्यमंत्री

वैसे तो संविधान में उपमुख्यमंत्री की भूमिका साफ़ नहीं है, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री जैसा ही पावर है, लेकिन भाजपा राज में उपमुख्यमंत्री तमगा ही नहीं लग रहा है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा को उपमुख्यमंत्री बनाया है। दोनों पहली बार के विधायक हैं। कहते हैं मुख्यमंत्री साय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा जिस तरह बैठकों में शामिल हो रहे और दिल्ली दौरे में साथ जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि राज्य में दोनों उपमुख्यमंत्रियों की अहम भूमिका रहने वाली है। भूपेश बघेल सरकार में आखिरी के कुछ महीनों में टीएस सिंहदेव उपमुख्यमंत्री बने थे, तब लोगों को उपमुख्यमंत्री का रोल समझ में नहीं आया था । टीएस सिंहदेव नाम के उपमुख्यमंत्री लगे थे।

प्रांत प्रचारक की पूछपरख

कहते हैं विष्णुदेव साय की सरकार में प्रांत प्रचारक प्रेम सिदार की पूछपरख बढ़ गई है। चर्चा है कि नेता-अफसर और दूसरे लोग भी जागृति मंडल के चक्कर काट रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव संघ की पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उनका झुकाव आरएसएस के प्रति काफी रहेगा। कहा जा रहा है कि 2003 से 2018 के भाजपा शासनकाल में संघ का रोल काफी ज्यादा नहीं था। तब संगठन महामंत्री सौदान सिंह ज्यादा पावरफुल थे। खबर है कि इस बार भाजपा सरकार को लाने में आरएसएस ने काफी मेहनत की, इस कारण सरकार में संघ का प्रभाव दिखेगा ही। इसको भांपते हुए नेता-अफसर प्रांत प्रचारक के दफ्तर में हाजिरी देने लगे हैं। कई विधायकों ने मंत्री बनने के लिए भी संघ दफ्तर के चक्कर काटे। इसका उन्हें कितना लाभ हुआ, वे ही बता सकते हैं।

नुकसान में रेणुका सिंह

केंद्र में मंत्री रही रेणुका सिंह राज्य में मंत्री भी नहीं बन पाई। मुख्यमंत्री के लिए रेणुका सिंह का नाम खूब चला। लोग मानने लगे थे कि केंद्र में राज्य मंत्री और आदिवासी होने के नाते रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बन जाएंगी। संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने रेणुका सिंह की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। लेकिन बाजी मार गए विष्णुदेव साय। कहते हैं परफॉर्मेंस और कार्यशैली रेणुका सिंह के रास्ते में बाधक बन गईं। यही वजह है कि भाजपा ने सरगुजा इलाके की लक्ष्मी राजवाड़े को महिला कोटे से मंत्री बनाया, पर रेणुका पर विचार ही नहीं किया। अब रेणुका सिंह विधायक बनकर समय काटेंगी। अब देखते हैं उनके अच्छे दिन कब लौटते हैं ?

बृजमोहन के नाम रिकार्ड ही रिकार्ड

भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने 2023 का विधानसभा चुनाव सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीतने का रिकार्ड बनाया ही। 1990 से लगातार विधायक बनने और हर भाजपा सरकार में मंत्री बनने का भी रिकार्ड बना लिया है। आठ बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल एक ही बंगले में रहने का रिकार्ड बनाने जा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल अभी शंकर नगर स्थित जिस बंगले में रहते हैं, उसमें वे 2003 से हैं। कांग्रेस की सरकार में भी उसी बंगले में रहे। अब मंत्री बन गए हैं तो बंगला रहेगा ही। बंगला नहीं बदला तो, एक ही बंगला में 25 साल तक रहने का रिकार्ड बना लेंगे। ऐसा रिकार्ड अब तक किसी के नाम पर दर्ज नहीं है।

भाजपा सरकार के पावर सेंटर

सरकार में सत्ता का केंद्र मुख्यमंत्री निवास तो होता ही है। विष्णुदेव साय सरकार में सीएम हाउस के अलावा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जागृति मंडल और वीआईपी रोड़ स्थित राममंदिर को पावर सेंटर बताया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, प्रदेश भाजपा मुख्यालय है, तो जागृति मंडल आरएसएस का मुख्यालय। वीआईपी रोड़ स्थित राममंदिर को संघ से जुड़े एक ताकतवर नेता का केंद्र बताया जाता है। इस ताकतवर नेता की सिफारिश पर कुछ लोगों को विधानसभा की टिकट मिली तो कुछ लोगों को भाजपा संगठन में पदाधिकारी बनाया गया है। कहते हैं निगम-मंडल में पद चाहने वाले और संगठन में पद के इच्छुक लोग असमंजस में हैं कि लक्ष्य पूर्ति के लिए कहां मत्था टेकें।

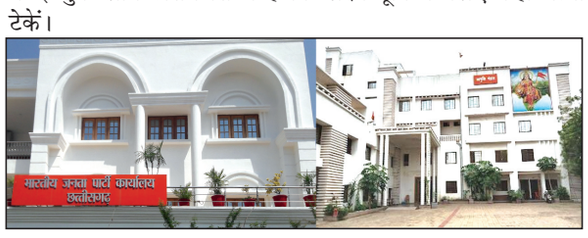

मंत्रियों के इंतजार में फाइलों का अंबार

कहते हैं नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को विभाग वितरित न होने से मंत्रालय और अलग-अलग विभागों में फाइलों का अंबार लग गया है। अक्टूबर में आचार संहिता लगने के बाद से ही सरकारी कामकाज ठप्प हैं। अब नई सरकार बनने के बाद भी सरकारी मशीनरी गति नहीं पकड़ सकी है। मंत्रालय में बैठे अफसर परिवर्तन के इंतजार में हैं तो जिले में तैनात अफसर भी भविष्य को लेकर सशंकित हैं। नई सरकार हड़बड़ी में कदम उठाने की जगह सब्र दिखा रही है। मुख्यमंत्री साय ने 2006 बैच के आईएएस पी दयानंद को अपना सचिव बनाने के साथ अपने स्टाफ में कुछ नियुक्तियां भी आनन-फानन में नहीं की। वहीं पुरानी सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात सचिवों के विभागों को यथावत रखा है। वे मुख्यमंत्री सचिवालय से तो अलग हुए, पर पुराने विभाग के सचिव बने हुए हैं।

नई सरकार में संविदा अफसर यथावत

राज्य में नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया है, लेकिन कांग्रेस राज में संविदा नियुक्त आईएएस - आईपीएस अपने पद पर यथावत बने हैं। नई सरकार के गठन के पहले ही संविदा नियुक्त आईएएस अफसर डॉ आलोक शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया। पर संविदा में नियुक्त आईएएस अमृत खलखो और डी डी सिंह यथावत अपने पद पर बने हैं। अमृत खलखो राज्यपाल के सचिव और समाज कल्याण विभाग के सचिव हैं। डी डी सिंह के पास सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का प्रभार है। रिटायरमेंट के बाद आईपीएस डी एम अवस्थी ईओडब्ल्यू के डीजी बने हैं। संविदा में कार्यरत आईपीएस संजय पिल्लै के पास डीजी जेल का प्रभार है।

कांग्रेस की बैठक में निकले पूर्व विधायकों के दिल के गुबार, गिले-शिकवे भूल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का किया फैसला

रायपुर। कांग्रेस के पूर्व विधायकों की बैठक हुई. शिशुपाल सोरी ने बताया कि बैठक में दिल के सारे गुबार निकल गए. हार को लेकर आंसू भी छलके. अब सारी बातें भूलकर लोकसभा की तैयारी में जुटेंगे. राजीव भवन में हुई कांग्रेस के पूर्व विधायकों की बैठक में सर्वे रिपोर्ट से टिकट काटने का मुद्दा फिर उठा. पूर्व विधायकों ने सर्वे रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए कहा कि अगर टिकट नहीं कटी होती तो फिर सरकार बनती. बैठक के बाद चंद्रदेव राय ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई. इतनी संख्या में टिकट नहीं कटी होती तो सरकार बन जाती. 7 घंटे से अधिक चली बैठकों में प्रदेश

कांग्रेस अध्यक्ष ने एक-एक जिला अध्यक्षों, टिकिट से वंचित विधायकों, संयुक्त महासचिव, सचिवों और मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बातों को विस्तार से सुना। इस दौरान पार्टी के संयुक्त महामंत्री, सचिव और पूर्व विधायकों ने जमकर भड़ास निकाली। कई कार्यकर्ताओं ने विधायकों के टिकट काटने लेकिन किसी मंत्री का टिकट नहीं काटने का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को एक पदाधिकारी ने कहा कि, 'आपसे क्या कहें, आप तो चार महीने पहले आए. चुनाव के दौरान जमकर भीतरघात हुई'. वहीं कुछ ने पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं पर जोगी कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। राजीव भवन में हुई कांग्रेस के पूर्व विधायकों की बैठक में सर्वे रिपोर्ट से टिकट काटने का मुद्दा फिर उठा। पूर्व विधायकों ने सर्वे रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए कहा कि अगर टिकट नहीं कटी होती तो फिर सरकार बनती। बैठक के बाद चंद्रदेव राय ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई। इतनी संख्या में टिकट नहीं कटी होती तो सरकार बन जाती।

कांग्रेस की अंर्तकलह खुलकर सामने आई-भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस की बैठक को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग सत्ता में रहते हुए तो जनता से कटे-कटे रहे ही, अब जबकि प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका है तब भी अपनी हार की समीक्षा करते हुए भी जनता के प्रति अपने गैर-जिम्मेदाराना राजनीतिक आचरण को लेकर उन्हें कोई मलाल नहीं है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जनता के प्रति गैर-जवाबदेही और अपने सत्तावादी अहंकार के लिए सत्ता का बेजा इस्तेमाल ही कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र रहा है, यह कांग्रेस की समीक्षा बैठक से प्रमाणित हो रहा है।

उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री से मिले मुख्यमंत्री

रायपुर (असं)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंदीय गृहमंत्री अमित शाह वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा भी उनके साथ थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करने 26 को कवि सम्मेलन

रायपुर। वीर बाल दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग, सामाजिक चेतना मंच और शिवाशा फाउंडेशन के द्वारा 26 दिसंबर को कवि सम्मेलन नवा सुरुज का आयोजन बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया गया है। जिसमें कवि डा. कुमार विश्वास, पद्मश्री डा. सुरेंद्र दुबे सहित देश के अन्य कवि अपनी कविताओं के माध्यम से उनकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कवि सुरेंद्र दुबे, उज्जवल दीपक, आशुतोष सुरेंद्र दुबे और कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रुप में छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा. रमन सिंह रहेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्खों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रुप में मनाने की घोषणा की थी। गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादों में से दो बड़े बेटों ने चमकौर के युद्ध में वीरतापूर्वक अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था जबकि दोनों छोटे साहबजादों को मुगल सूबेदार वजीर खान ने इस्लाम धर्म ना कबूल करने की वजह से जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था।

कांग्रेसियों को मनमुताबिक ट्रांसफर-पोस्टिंग न करा पाने का रंज है

रायपुर। कांग्रेस के लोग सत्ता में रहते हुए तो जनता से कटे-कटे रहे ही, अब जबकि प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका है तब भी अपनी हार की समीक्षा करते हुए भी जनता के प्रति अपने गैर-जिम्मेदाराना राजनीतिक आचरण को लेकर उन्हें कोई मलाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जनता के प्रति गैर-जवाबदेही और अपने सत्तावादी अहंकार के लिए सत्ता का बेजा इस्तेमाल ही कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र रहा है, यह कांग्रेस की समीक्षा बैठक से प्रमाणित हो रहा है। श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री और सचिव की मौजूदगी में हुई कांग्रेस की बैठक में पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता एक-दूसरे पर पार्टी के साथ जमकर गद्दारी करने का आरोप लगा रहे हैं और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इसकी तस्दीक की है। आलम यह है कि कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, निगम-मंडल अध्यक्षों पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है। श्री श्रीवास्तव ने इस बात पर हैरत जताई कि कांग्रेस के लोगों का यह गुस्सा इस बात पर कतई नहीं है कि कांग्रेस की भूपेश सरकार के मंत्री, निगम-मंडल अध्यक्ष जनता के हित का काम नहीं किया बल्कि यह गुस्सा इस बात का है कि कांग्रेस के शासनकाल में उनके मनमुताबिक अफसरों-कर्मियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं हुई।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद का किया निरीक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा आज जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद का निरीक्षण किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति के साथ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री अरविन्द कुमार वर्मा और डिप्टी रजिस्ट्रार कम माननीय श्री न्यायमूर्ति के पी.पी.एस.एम. व्ही.एल.एन. सुब्रम्हण्यम भी उपस्थित रहे। श्री रमेश सिन्हा द्वारा जिला अधिवक्ता संघ बालोद के सभाकक्ष में समस्त अधिवक्तागण को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की उपस्थिति में संबोधित किया गया और अधिवक्ताओं से भी चर्चा की। उन्होंने न्यायालय परिसर का सम्पूर्ण निरीक्षण कर कहा कि न्यायालय परिसर छोटा है, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से सम्पूर्ण कार्य संपादन संचालित किए जा रहे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रज्ञा पचौरी द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि नवीन न्यायालय निर्माण हेतु भूमि आबंटित हो चुका है। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि आबंटित भूमि में बिल्डिंग निर्माण के लिए लगभग 15.27 करोड़ रूपए स्वीकृत हो चुके हैं।

खिलाड़ियों की ऐसी दुर्दशा क्यों? बाथरूम के पास बैठकर दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक करना पड़ा सफर

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं. लेकिन उनकी अगर सही ठंग से खाने-पीने और आने जाने जैसी व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं मिले तो ये बड़ा अन्याय है. एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें कड़के की ठंड में महिला खिलाड़ियों को दिल्ली से पेंड्रारोड तक ट्रेन में बाथरूम के पास फर्श पर बैठकर सफर करना पड़ा. यह नजारा छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का है. इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है बाथरूम की गंदी बदबू के बीच छात्राएं सफर कर रही है. जानकारी के अनुसार, 14 से 17 और आयु 19 आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जिमनास्टिक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की 51 महिला खिलाड़ी भाग लेने गई थीं. दिल्ली से वापस प्रदेश आने के लिए खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति (12824) में भेड़-बकरियों की तरह सफर करना पड़ा. खिलाड़ियों को बाथरूम की गंदगी के बीच ट्रेन में फर्श पर बैठकर यात्रा करना पड़ा. बताया जा रहा है कि ये सारी छात्राएं हजरत निजामुद्दीन से पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन तक का सफर बोगी में नीचे बैठकर यात्रा की. जो कि खिलाड़ियों के लिए ठंड के मौसम में बेहद कठिन और कष्टदायक अनुभव रहा.

नॉन इंटरलॉकिंग कार्य -यह ट्रेन रायपुर, रायगढ़ के रास्ते पहुंचेगी विजयनगरम

रायपुर। दक्षिण मध्य रेलवे के काजीपेट-बल्हारशाह सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण गांधीधाम-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और ओखा-पुरी एक्सप्रेस ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी. 7 जनवरी 2024 को गांधीधाम से चलने वाली ट्रेन संख्या 20804 गांधीधाम-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग सूरत-बल्लारशाह-विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया नागपुर-रायपुर-टिटिलागढ़-रायगढ़-विजयनगरम के रास्ते चलेगी. यह ट्रेन वर्धा-चंद्रपुर-बल्हारशाह-सिरपुर कागजनगर-रामगुंडम-वारंगल-खम्मम-विजयवाडा-एलुरु-राजमंड्री-सामलकोट-दुव्वाडा स्टेशनों पर नहीं जाएगी. वहीं, 4 और 11 जनवरी 2024 को विशाखापट्टनम से चलने वाली ट्रेन संख्या 20803 विशाखापट्टनम-गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग विशाखापट्टनम-विजयवाड़ा-बल्हारशाह-सूरत के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया विजयनगरम-रायगढ़-टिटिलागढ़-रायपुर-नागपुर के रास्ते चलेगी. यह ट्रेन दुव्वाडा-सामलकोट-राजमंड्री-एलुरु- विजयवाडा-खम्मम-वारंगल-रामगुंडम-सिरपुर कागजनगर-बल्हारशाह-चंद्रपुर-वर्धा स्टेशनों पर नहीं जाएगी. इसके साथ ही 3 और 10 जनवरी 2024 को ओखा से चलने वाली ट्रेन संख्या 20820 ओखा-पुरी एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग सूरत-बड़नेरा-बल्हारशाह-विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम-खुर्दा रोड के स्थान पर परिवर्तित मार्ग नागपुर-रायपुर-टिटिलागढ़-रायगढ़-विजयनगरम के रास्ते चलेगी.

कोई भी पीवीटीजी हितग्राही वन अधिकार से ना हो वंचित

रायपुर। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजनांतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित विभागीय अधिकारियों से कहा गया कि कोई भी पीवीटीजी हितग्राही वनाधिकार से वंचित न रहे। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर के ऑडिटोरियम में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हुआ। आज की कार्यशाला व्यक्तिगत वनाधिकार धारकों

को विभागीय अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण पर केन्द्रित रही। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अपर संचालक श्री संजय गौड़ ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण का शत प्रतिशत लाभ विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को दिलाने हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने पीवीटीजी क्षेत्रों में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के वितरण पर ध्यान देने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में पैदा हो रहे मिलेट्स के संग्रहण पर भी प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण में लगभग 23 हजार से अधिक वन अधिकार पत्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के हितग्राहियों को प्रदाय किए गए हैं। सर्वेक्षण का कार्य जारी है, शीघ्र ही अन्य हितग्राहियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। श्री गौड़ ने बताया कि पीवीटीजी क्षेत्रों होने वाले सर्वे में मिलेट्स को प्रमुखता से शामिल किया जाए, क्योंकि जो पीवीटीजी इनके उत्पादन एवं संग्रहण में लगी हुई हैं, उन्हें इसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके। यह प्रयास पीवीटीजी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में अहम सिद्ध होगा। उपायुक्त श्री प्रज्ञान सेठ ने कार्यशाला में बताया कि पीएम जनमन योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इसके लिए ग्राम स्तर पर पीवीटीजी बसाहटों में जाकर सर्वे कर अधोसंरचनात्मक कमियों की जानकारी प्राप्त करनी होगी।

जिस देश में महिलाओं को बराबरी का स्थान मिलता है वह देश उन्नति की शिखर पर होता हैं-शुक्ल

रायपुर। श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति सच्चिदानंद शुक्ल थे। इस दौरान कार्यकम की अध्यक्षता राष्ट्रीय विद्यालय समिति के अध्यक्ष अजय तिवारी के द्वारा की गई।

इस अवसर पर कार्यकम में उपाध्यक्ष श्री गोवर्धन दास डागा श्री मदन लाल तालेडा, सचिव श्री अनिल कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री राज किशोर नत्थानी, श्री देवीचंद श्रीश्रीमाल. श्री रूपचद श्रीश्रीमाल श्री सुरेश शुक्ला, डागा महाविद्यालय प्राचार्या श्रीमती संगीता घई प्राचार्य प्रोफेसर डा गायत्री शर्मा सांस्कृतिक कार्यकम प्रभारी रेणुका बक्षी, के साथ अन्य प्राध्यापकगण के अलावा कालेज की छात्राएं आदि उपस्थित थे। कार्यकम की शुरूआत मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलन के साथ हुई। जिसके बाद महाविद्यालय की प्राचार्या डा श्रीमती संगीता घई के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समिति अध्यक्ष अजय तिवारी अपने अध्यक्षयीय उदबोधन ने कहा कि वार्षिक उत्सव कार्यक्रम अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का अवसर होता है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.